रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1978/ आश्विन 8, 1900
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1978/ASVINA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1978

का०आ० 2849.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 158–बुरटोला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमलेन्दु राय, 5/1, हरिपाल लेन, कलकत्ता-6 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमलेन्दु राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० प० बं०-वि० स०/158/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 28th August, 1978

S.O. 2849.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amalendu Roy, 5/1, Haripal Lane, Calcutta-6, a contesting candidate for general election the West Bengal Legislative Assembly from 158-Burtola assembly constituency, held in June, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amalendu Roy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/158/77]

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1978

का० आ० 2850.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 1-मेकलीगंज (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुभाष चन्द्र मैत्रा, गांव-उत्तर बारा हल्दीबारी (सान्तीनगर) डा० हल्दी बारी, जिला कूच बिहार, पश्चिमी बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुभाष चन्द्र मैत्रा, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या प० बं०-वि सं० 1/77]

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1978

S.O. 2850.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Subhash Chandra Maitra, Village Uttar Bara Haldibari (Santinagar), P.O. Haldibari, District Cooch Behar, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 1-Mekhganj (SC) assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And, whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Subhash Chandra Maitra, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/1/77]

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1978

का० आ० 2851.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 209-खजूरी (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जलाधर पात्र, गांव गौरंग, पी० ओ० कार्तिक खाली, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जलाधर पात्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या प० बं०-वि० स०/209/77]

ORDER

New Delhi the 30th August, 1978

S.O. 2851.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaladhar Patra, Village Corrang, P. O. Kartick Khali, District Midnapore, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 209-Khajuri (SC) assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaladhar Patra, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/209/77]

आदेश

का० आ० 2852.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए, पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 229-न्याग्राम (अ० ज० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री किशनू मुरमू, गांव मोहनपुर, डाकघर चिलकी-पाड़ा, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री किशनू मुरमू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या प० बं० वि० सं०/229/77]

ORDER

S.O. 2852.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishnu Murmu, Village Mohanpur, P. O. Chilkipada, District Midnapur, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 229-Nayagram (ST) assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

[No. WB-LA/229/77]

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1978

का० आ० 2853.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 214-मुगबेरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमिया कुमार बाग, गांव-उत्तर बरोज, डा० कयमगेरिया, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमिया कुमार बाग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या प० बं०-वि० स०/214/77]

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1978

S.O. 2853.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Amiya Kumar Bag, Village Uttar Baroj, P.O. Kayemgoria, District Midnapore, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 214-Mugberia assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amiya Kumar Bag, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/214/77]

आदेश

का० आ 2854.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 202–तामलुक निर्वाचन-क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बनेश्वर दास, गांव-पाडुम्बासन, डा० तामलुक, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बनेश्वर दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या प० बं०-वि० स० 202/77]

ORDER

S.O. 2854.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Baneswar Das, Village Padumbasan, P.O. Tamluk, District Midnapore, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 202-Tamluk assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baneswar Das, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/202/77]

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1978

का०आ० 2855.—निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो चुका है कि जून 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए पंजाब के 103–कोट कपूरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वजीर चन्द सुपुत्र श्री सन्त राम, प्रोप्राइटर शक्ति सरजीकल्स, जैतू, तह० फरीदकोट, जिला फरीदकोट (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वजीरचन्द सुपुत्र श्री सन्त राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० पंजाब वि० स०/103/77]

बी० सागभूषणम्, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1978

S.O. 2855.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Wazir Chand S/o. Shri Sant Ram, Prop, Shakti Surgicals, Jaitu, Tahsil Faridkot, District Faridkot (Punjab) who was a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly from 103-Kot Kapura held in June, 1977 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Wazir Chand S/o Shri Sant Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/103/77]
V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

New Delhi, the 13th September, 1978

S.O. 2856.—In pursuance of section 111 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) the Election Commission hereby publishes the report dated 26th July, 1978 of the High Court at Calcutta in Election Petition No. 4 of 1977.

High Court
G.P.O.
Calcutta-700001.

No. C.R. 4228

FROM:

Shri S. K. Bose, LL.B. Attorney-at-law & Advocate Dy. Registrar, High Court at Calcutta, Original Side,

To

The Election Commissioner of India,
Ashok Road, New Delhi-110001.

Dated, Calcutta, the 26th July, 1978

Sir,

Re:—In the matter of:

Election Petition Case No. 4 of 1977 in Andaman and Nicobar Islands, Parliamentary Constituency held on 16th March, 1977.

AND

In the matter of:

An Election Petition under Representation of the People Act, 1951 (Act 43 of 1951).

AND

In the matter of K. R. Ganesh alias Khem Raj Ganesh.

Versus

Monoranjan Bhakta & Anr.

I am to inform you that on 22-3-1978 Shri Khem Raj Ganesh, the petitioner in the above Election Petition Case filed a petition before this Court praying inter alia, for withdrawing the above Election Petition Case instituted on 5-5-1977 against the said respondents. On the said petition His Lordship the Hon'ble Mr. Justice Sabyasachi Mukherji was pleaded to pass an order on 27-6-1978 an authenticated copy whereof is forwarded herewith.

In this connection I am to state that no substitution having been made herein in terms of Section 111 of the Representation of the People Act, 1951 the said order may be treated to have been made under the said section.

Yours faithfully,
Sd/- (S. K. Bose)
26-7-1978
Deputy Registrar.

Encls:—As above.

Election Petition Case No. 4 of 1977

HIGH COURT AT CALCUTTA

ELECTION PETITION JURISDICTION

In the Matter of:

K. R. Ganesh alias Khem Raj Ganesh . . .Petitioner

Versus

Monoranjan Bhakta and another Andaman and Nicobar Islands Parliamentary constituency.

. .Respondents.

Noting by Office or Advocate	Serial No.	Date	Office notes reports, orders or proceedidgs with signatures
		27.6.78	Mr. Tapas Palit appears submits. Mr. Ajit Panja appears for the Respdt. No. 1 submits. Mr. Shymal Ganguli appears for the Respdt. No. 2 submits. The Court: Leave granted to withdraw the Election Petition in terms of prayer (a) of the Petition. Order In terms of prayer (b) of the petition. Copy of the Calcutta Gazette dt. 4.5.78 produced to-day to be kept with the records.

In view of the above order there will be no order on the petition of the Respondent No. 1 dated 19th September 1977.

All necessary steps to be taken by the Registrar, O.S. to send a report of withdrawal with a copy of the order made this day to the Election Commissioner for publication in the Official Gazette.

Sabyasachi Mukharji,
[No. 82/A&NI/(4/77)/78]
T. NAGARATHNAM, Secy.

वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

का०आ० 2857.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है:

उपक्रमों के नाम	पंजीकरण संख्या
(1) मैसर्स स्टिरलिंग रि-रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	639/70
(2) मैसर्स निर्मल एंड एसोसियेट्स	638/70
(3) मैसर्स माडर्न फेमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	642/70
(4) मैसर्स विनय ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	637/70
(5) मैसर्स रुइया इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०	636/70
(6) मैसर्स हैल्थ प्रोडक्ट्स प्रा०लि०	643/70
(7) मैसर्स रुइया स्टूड एण्ड एग्रीकल्चरल फार्मस प्रा०लि०	640/70

[सं० 2/22/78-एम० 2]
एच० के० जैन, उप सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 2857.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969),the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of the following undertakings under the said Act.

Name of the undertakings	Registration No.
1. M/s. Sterling Re. Rolling Mills Pvt. Ltd.	639/70
2. M/s. Nirmal & Associates	638/70
3. M/s. Modern Family Planning Products Ltd.	642/70
4. M/s. Vinaya Trading Co. Pvt. Ltd.	637/70
5. M/s. Ruia Industries Pvt. Ltd.	636/70
6. M/s. Health Products Pvt. Ltd.	643/70
7. Suia Stud and Agricultural Farms Pvt. Ltd.	640/70

[F. No. 2/22/78-M. II]
H. K. JAIN, Dy. Secy.

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का०आ० 2858.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री ओम प्रकाश जैन, एडवोकेट, 25-बी/126-बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, दिल्ली में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[सं० 22/49/78-न्याय]

एल० डी० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2858.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Om Parkash Jain, Advocate, A.5 B/126B, Janak Puri, New Delhi for appointment as a Notary to practice in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/49/78-Just.]
L. D. HINDI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1978

का०आ० 2859.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों की बाबत नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में, नियम 15 के उपनियम (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि कोई सरकारी सेवक—

(i) किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्त सोसाइटी या कम्पनी, क्लब अथवा ऐसे ही संगठन के जिसके लक्ष्य और उद्देश्य खेल-कूल, संस्कृतिक या मनोरंजक क्रिया कलापों को बढ़ावा देना हो और जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों; या

(ii) सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो सारतः सरकारी सेवकों के लाभ के लिये हो;

रजिस्ट्रीकरण, प्रोन्नति और प्रबंध में भाग ले सकता है ।"

[सं० 11013/3/78 स्थापना(ए)]
आर० सी० गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 20th September, 1978

S.O. 2859.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, and in consultation with the Comptroller and Auditor-General in regard to the employees of the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following further amendments in the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, for the proviso to sub-rule (3) of rule 15, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that a Government servant may take part in the registration, promotion or management of—

(i) a literary, scientific, or charitable society or of a company, club or similar organisation the aims and objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or the Companies Act, 1956, or any other law for the time being in force; or

(ii) a co-operative society substantially for the benefit of Government servants registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force."

[No. 11013/3/78-Estt(A)]
R. C. GUPTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1978

का०आ० 2860.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध 1 मार्च, 1978 से 28 फरवरी, 1979 तक की अवधि के लिए सेफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई पर लागू नहीं होंगे ।

[संख्या 8-1/78-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 14th September, 1978

S.O. 2860.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to Safe Co-operative Bank Ltd., Bombay for the period from 1 March 1978 to 28 February, 1979.

[No. 8-1/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1978

का० आ० 2861.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (य ख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कलाविहार को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई विषयक भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 23 जून, 1978 के स्थगन आदेश संख्या एफ० 8-17/78-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेशों में अंकों, वर्णों और शब्दों "23 सितम्बर, 1978" के स्थान पर अंक, वर्ण और शब्द "23 दिसम्बर, 1978" प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[संख्या एफ० 8/14/78-ए० सी०]

महावीर प्रसाद वर्मा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2861.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 read with clause (zb) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government hereby makes the following amendment in the order of moratorium of the Government of India in the Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 8-14/78-AC dated 23rd June 1978 in respect of the Kalavihar Co-operative Bank Ltd. Bombay namely :—

In the said order, for the figures, letters and words "23rd September 1978" the figures, letters & words "23rd December 1978" shall be substituted.

[No. F. 8/14/78-AC]

M. P. VERMA, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, अहमदाबाद

अहमदाबाद, 2 सितम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

का० आ० 2862.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 8 की उपधारा (क) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, के० श्रीनिवासन, समाहर्ता सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, अहमदाबाद इसके द्वारा, भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० 255(ई) दिनांक 1 मई, 1978 में निर्धारित की गई काण्डला बन्दरगाह की सीमा के अन्दर कच्छ की खाड़ी (समुन्द्र) में आफ शोर टर्मिनल स्टेशन को अपरिष्कृत (क्रूड) पेट्रोलियम उतारने (अनलोडिंग) के स्थान के रूप में अनुमोदन करता हूं ।

[सं० 4/78-सी० शु० फा० सं० आठ/48-194/सी० शु० 77]

(Department of Revenue)

(Customs and Central Excise Collectorate, Ahmedabad)

Ahmedabad, the 2nd September, 1978

CUSTOMS

S.O. 2862.—In exercise of the powers conferred on me under sub-section (a) of section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, K. Srinivasan, Collector of Customs & Central Excise, Ahmedabad hereby approve the Off Shore Terminal Station in the Gulf of Kutch within the port limits of Kandla laid down under Notification No. 255(E) dated 1st May, 1978 issued by the Government of India, Ministry of Shipping & Transport, New Delhi as a landing place for unloading of Crude petroleum.

[No. 4/78-Customs/F. No. VIII/48-194/Cus./77]

सीमा-शुल्क

का० आ० 2863.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के साथ पठित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) नई दिल्ली की दिनांक 18-7-75 की अधिसूचना सं० 79-सी० शु० फा० सं० 473/2/75-सी० शु०-II के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, के० श्रीनिवासन, समाहर्ता, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अहमदाबाद, इसके द्वारा, गुजरात राज्य के काण्डला बन्दरगाह की सीमा (जो भारत सरकार, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं० 255(ई) दिनांक 1-5-78 में निर्धारित की गई है) के अन्दर वाडीनार के बन्दरगाह को अपरिष्कृत (क्रूड) पेट्रोलियम के भण्डार के लिए भाण्डागार (बेयर हाउसिंग) स्थान बनाने के लिए अनुमोदन करता हूं ।

[सं० 5/78-सी० शु० फा० सं० III/48-194/सी० शु०/77]

के० श्रीनिवासन, समाहर्ता

CUSTOMS

S.O. 2863.—In exercise of the powers conferred on me under section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with the Notification No. 79-Cus., F. No. 473/2/75-Cus. VII dated 18-7-1975 issued by the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue & Insurance), New Delhi, I, K. Srinivasan, Collector of Customs & Central Excise, Ahmedabad, hereby declare the port of "VADINAR" falling within the limits of Kandla port (as laid down in Notification No. 255(E) dated 1-5-78 issued by the Government of India, Ministry of Shipping and Transport, New Delhi) in the State of Gujarat, to be a warehousing station for storage of crude petroleum.

[No. 5/78-Customs/F. No. VIII/48-194/Cus./77]

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

का०आ० 2864.—केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि कतीरा (गम कराया) निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें जैसा कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित है निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, उक्त उप-नियम (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2453, तारीख 12 अगस्त, 1966 का अधिक्रमण करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है;

2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि कतीरा (गम कराया) निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगा;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध-I में दिए गए कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे कतीरा (गम कराया) पर निर्यात के पूर्व लागू होगा;

(3) इस आदेश के उपाबन्ध-II में दिए गए विनिर्देशों को कतीरा (गम कराया) के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे किसी भी कतीरा (गम कराया) के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसा कतीरा (गम कराया) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से सम्बन्धित शर्तों की पूर्ति करता है और निर्यात योग्य है ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, जल या वायु मार्ग द्वारा कतीरा (गम कराया) के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी, परन्तु यह तब जब ऐसे नमूने का भार एक किलोग्राम से अधिक नहीं है ।

4. इस आदेश में कतीरा (गम कराया) से स्टीरकूलिया अनरस पौधे से प्राप्त गोंद अभिप्रेत है ।

उपाबन्ध I

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 को अभिव्यक्त करते हुए बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम कतीरा (गम कराया) निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है ।

(2) ये .....को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है;

(ग) 'कतीरा' से स्टीरकूलिया अनरस पौधे से प्राप्त गोन्द अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार : कतीरा (गम कराया) का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : कतीरा (गम कराया) के निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण को देगा और ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा करेगा कि कतीरा (गम कराया) का परेषण नियम 3 के अनुसार तैयार किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

2. जहां निर्यातकर्ता की यह इच्छा है कि निर्यात किए जाने वाले कतीरा (गम कराया) के परेषण का निरीक्षण—

(क) बम्बई में अभिकरण द्वारा किया जाए वहां वह उप-नियम (1) के अधीन पोत लदान से कम से कम तीन दिन पहले सूचना देगा ।

(ख) कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली या मद्रास में अभिकरण द्वारा किया जाए वहां वह पोत लदान से कम से कम 7 दिन पहले उप-नियम (1) के अधीन सूचना देगा ।

(3) (i) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने पर, अभिकरण कतीरा (गम कराया) के परेषण का निरीक्षण निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार अपना यह समाधान करने के विचार से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत तथा पैक किया गया है ।

(ii) निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने योग्य बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।

4. यदि निरीक्षण के पश्चात् अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किए जाने वाले कतीरा (गम कराया) का परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन में है तो अभिकरण परेषण को निर्यात योग्य घोषित करने वाला प्रमाण-पत्र—

(i) बम्बई में अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की दशा में, सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर जारी करेगा; और

(ii) कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली या मद्रास में अभिकरण द्वारा निरीक्षण किए जाने की दशा में सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर जारी करेगा :

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह यथास्थिति, उक्त तीन दिन या सात दिन के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करेगा तथा ऐसे इन्कार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को भेजेगा ।

5. पैकिंग : कतीरा (गम कराया) दोहरे पट के बोरों में पैक होगा जबकि अन्दर का बोरा साफ और मजबूत होगा, बाहरी बोरा पूरी तरह नया होगा ।

6. निरीक्षण का स्थान: (i) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर पर किया जाएगा जबकि निरीक्षण के लिए माल प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों;

(ii) निर्यातकर्ता के परिसर पर निरीक्षण के अतिरिक्त, अधिकरण पोत-लदान के समय गोदामों या घाट पर भी परेषण का निरीक्षण कर सकता है ।

7. निरीक्षण की फीस: इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए 50 रुपए की न्यूनतम राशि की सीमा में रहते हुए पोत-लदान पर्यन्त: निःशुल्क मूल्य 5 की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में की जाएगी ।

8. अपील: (i) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपाबन्ध-II

कतीरा (गम कराया) के लिए विनिर्देश

1. गोन्द स्टीरकूलिया अनरस पौधे से प्राप्त किया जाएगा ।

2. गोन्द निम्नलिखित श्रेणी मानकों के अनुरूप होगा:

श्रेणी	रंग	छाल और बाह्य कार्बनिक पदार्थ (अ प्रकार)
सं० 1 हल्के धूसर के साथ सफेद	0.5	अधिकतम
सं० 2 बहुत हल्का भूरा	1.5	अधिकतम
सं० 3 भूरा	3	अधिकतम
मध्यम गहरा भूरा	10.0	अधिकतम

3. गोंद क्रेता तथा विक्रेता के बीच तय निर्यात संविदा में अधिकथित आकार के अनुसार होगा ।

4. गोन्द कुन्तक उत्सर्ग, कुन्तक मैल और कुन्तक बालों से मुक्त होगा ।

[सं० 6(9)/77-नि० नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कूकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1978

S.O. 2864.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Gum Karaya shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule (2), the Central Government, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2453 dated the 12th August, 1966, publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this Order to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001

PROPOSALS

(1) To notify that gum karaya shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) to specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1978, set out in Annexure-I to this Order as the type of inspection which would be applied to such gum karaya prior to export;

(3) to recognise the specifications set out in the Annexure-II to this Order as the standard specifications for gum karaya;

(4) to prohibit the export in the course of international trade of any such gum karaya unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such gum karaya satisfies the conditions relating to quality control and inspection and is export-worthy.

3. Nothing in this order shall apply to export by sea, land or air of samples of gum karaya to prospective buyers, provided that no such sample is in excess of one kilogram in weight.

4. In this order 'Gum Karaya' shall mean the gum obtained from the plant Sterculia Urens.

ANNEXURE—I

Draft Rules proposed to be made in supersession of the Export of the Gum Karaya (Inspection Rules 1965 under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on.....

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) "agency" means any one of the agencies, established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Gum Karaya" means the gum obtained from the plant Sterculia Urens.

3. Basis of inspection.—The quality control and inspection of gum karaya shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications, recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) Any exporter intending to export gum karaya shall give intimation in writing of his intention to do so to the agency and submit along with such intimation a declaration that the consignment of gum karaya has been prepared in accordance with rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specification recognised for the purpose.

(2) Where the exporter desires that the inspection of the consignment of gum karaya to be exported may be conducted,—

(a) by the agency at Bombay, he shall submit the intimation under sub-rule (1) not less than three days prior to shipment;

(b) by the agency at Calcutta, Cochin, Delhi or Madras he shall submit the intimation under sub-rule (1) not less than seven days prior to shipment.

(3) (i) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the agency shall inspect the consignment of gum karaya as per instructions issued by the Export Inspection Council, in this behalf, from time to time with a view to satisfying itself that the consignment has been graded and packed in accordance with rule 3.

(ii) The exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If after inspection, the agency is satisfied that the consignment of gum karaya to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, the agency shall issue a certificate declaring the consignment as exportworthy :—

(i) within three days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the agency at Bombay, and

(ii) within seven days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the agency at Calcutta, Cochin, Delhi or Madras,

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days or as the case may be, seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons thereof.

5. Packing.—The gum karaya shall be packed in double gunny bags. Whilst the inner bag shall be clean and sound, the outer bag shall be completely new.

6. Place of inspection.—(i) Inspection for the purposes of these rules shall be carried out at the premises of the exporter while the goods are offered for inspection provided adequate facilities exist therein for inspection.

(ii) In addition to the inspection at the exporter's premises, the agency may also inspect the consignments at the time of shipment in godown or at the wharf.

7. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 50 for each consignment, a fee at the rate of 5 per cent of F.O.B. value shall be paid as inspection fees under these rules.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the Panel of Experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE—II

SPECIFICATIONS FOR GUM KARAYA

1. The gum shall be obtained from the plant Sterculia Urens.

2. The gum shall conform to the following grade standards :

Grade	Colour	Bark and Foreign Organic Matter (B' Form)
No. 1	White with slight Grey Cast	0.5% Max.
No. 2.	Very Light Tan	1.5% Max.
No. 3.	Tan	3% Max.
Middlings	Dark-brown	10.0% Max.

3. The size of the gum shall be as agreed to between the buyers and the seller as laid down in the export contract.

4. The gum shall be free from rodent excreta, rodent filth and rodent hair.

[No. 6(9)/77-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Dy. Director

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

का०आ० 2865.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 में—

(क) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

16. लेखाओं की परीक्षा—(1) परिषद् सभी प्राप्त तथा खर्च की गई धन राशियों के लिए सभी संव्यवहारों के संबंध में, तथा ऐसे मामलों में, जिनके संबंध में आय तथा व्यय होते हैं, सभी क्रय तथा विक्रय, आस्तियों तथा दायित्वों की बाबत उचित लेखा-बहिया रखेगा ताकि परिषद् तथा इसके कार्यालयों की कार्यस्थिति का ठीक तथा उचित पता चल सके तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा विहित क्रमशः प्ररूप 3 तथा 4 में दिये गये अथवा संबंधित परिस्थितियों में अनुज्ञेय उससे यथासंभव मिलते जुलते प्ररूप में दिए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेगा और आय तथा व्यय का लेखा तथा तुलन-पत्र तैयार करेगा तथा ऐसे आय व्यय के लेखे तथा तुलन-पत्र पर परिषद् की ओर से सचिव तथा परिषद् के अपर निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टीरत लेखापालों द्वारा प्रतिवर्ष परिषद् के ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा की जाएगी तथा ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में हुए खर्च परिषद् द्वारा ही देय होंगे।

(3) उप-नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त चार्टीरत लेखापालों को ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जैसे कि ऐसे अन्य संगठनों के लेखापालों द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में प्रयोग, उपयोग तथा प्रवर्तित किये जाते हैं तथा विशेष रूप से उन्हें बहियों, लेखाओं से संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों तथा कागजात मंगवाने तथा परिषद् के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) इस निमित्त चार्टीरत लेखापालों द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखे, उन पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे तथा सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ख) प्रकप 2 के पश्चात्, अन्त में निम्नलिखित प्ररूप 3 और 4 अन्त स्थापित किये जाएंगे; अर्थात् :—

प्ररूप– 3

[नियम 16(1) देखिए]

निर्यात निरीक्षण परिषद्

———— को समाप्त होने वाले वर्ष की आय तथा व्यय का लेखा

व्यय			आय		
पूर्वतन वर्ष के लिए अंक (रु०)	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिये अंक (रु०)	पूर्वतन वर्ष के लिये अंक (रु०)	विशिष्टियां (रु०)	चालू वर्ष के लिये अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. स्थापन			1. सरकारी अनुदान से भिन्न आय	
	अधिकारियों का वेतन			विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा	
	कर्मचारिवृन्द का वेतन			भेजे गए प्रार्थनापत्रों के शुल्क	
	महंगाई भत्ता			अधिमानता की सामन्यीकृत प्रणाली के	
	अन्य भत्ते (नगर प्रतिकरात्मक			अधीन मूल स्थान का प्रमाण-पत्र	
	भत्ता, मकान किराया भत्ता)			जारी करने से प्राप्त शुल्क	
	(क) अधिकारियों			विदेश सेवा अंशदानों से प्राप्त	
	(ख) कर्मचारिवृन्द			ब्याज से	
	(ग) परिषद् तथा अन्य समिति			अन्य आय से (विनिर्दिष्ट की जाएं)	
	के सदस्यों के लिये यात्रा भत्ता			विविध	
	चिकित्सा सहायता			2. सरकारी अनुदान	
	कर्मचारियों के कल्याणार्थ सहायता			3. विपणन विकास से अनुदान	
	परिषद् में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों			निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा चालू	
	को छुट्टी वेतन तथा पेंशन या			विभिन्न पूर्व पोत-लदान निरीक्षण	
	इसके समतुल्य अंशदान अंश-			योजनाओं के कार्य में हुए घाटे को	
	दायी भविष्य निधि में परिषद्			पूरा करने के लिये सरकार से प्राप्त	
	का अंशदान			4. आय की तुलना में कितना व्यय अधिक	
	अन्य स्थापन प्रभार			हुआ जो तुलन-पत्र पर लाया गया।	
	(विनिर्दिष्ट किए जाएं)				
	2. अन्य प्रभार				
	लेखन सामग्री				
	छपाई तथा जिल्द				
	डाक तथा तार व्यय				
	कार्यालय का किराया				
	विद्युत् प्रभार				
	टेलीफोन				
	लेखा परीक्षा शुल्क				
	मरम्मत और नवीकरण				
	भर्ती के लिए विज्ञापन				
	चन्दा और सदस्यता शुल्क				
	स्थानीय परिवहन प्रभार				
	मूल्य वृद्धि				
	व्यय की अन्य विनिर्दिष्ट मदें				
	विविध				
	प्रचार				
	विपणन विकास-कोष—विभिन्न पूर्व				
	पोत लदान निरीक्षण योजनाओं				
	के कार्य में हुए घाटे को पूरा करने				
	के लिए निर्यात निरीक्षण अभि-				
	करणों को भुगतान				
	विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम				
	विदेश से प्रशिक्षणार्थियों के लिये				
	प्रशिक्षण का कार्यक्रम				
	समितियों/परिषद्/अन्य समान				
	विदेशी संस्थाओं में भाग लेना				

1	2	3	4	5	6
	व्यापार मेला/प्रतिनिधि–मण्डल में भाग लेना				
	अधिमानता की समान्यीकृत प्रणाली के अधीन मूल स्थान का प्रमाण-पत्र				
	सेमिनार अभिसमयों और इसी तरह की अन्य गतिविधियों का संगठन				
	अन्य विनिर्दिष्ट खर्चे				
	आय की तुलना में कितना व्यय अधिक हुआ जो तुलन पत्र में लाया गया				

प्ररूप — 4

[नियम 16 (1) देखिए]

निर्यात निरीक्षण परिषद्

..... को तुलन पत्र

पूर्वतन वर्ष के लिये अंक (रु०)	दायित्व	चालू वर्ष के लिये अंक (रु०)	पूर्वतन वर्ष के लिये अंक (रु०)	आस्तियां	चालू वर्ष के लिए अंक (रु०)
	1. पूंजी खाता––(आय और व्यय खाते से अन्तरित उतनी रकम का अतिशेष जितनी व्यय की तुलना में आय से और आय की तुलना में व्यय से अधिक है			1. स्थिर आस्तियां (जहां तक सम्भव हो सके, मदों के खर्चे में भेद करते हुए)	
	2. संचिति तथा अधिक्य (यदि ऐसा सृजित किया गया है तो विनिर्दिष्ट करें)			2. विनिधान	
	3. प्रतिभूत ऋण			3. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम धन	
	4. अप्रतिभूत ऋण			(क) चालू आस्तियां, ऋण	
	5. चालू दायित्व तथा व्यवस्था			विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज	
	(क) चालू दायित्व			स्टाक और भंडार	
	कर्मचारियों को संदेय वेतन और अन्य वैयक्तिक दावे			फुटकर ऋणी	
	अंशदायी भविष्य निधि			अभिवहन में चैक ड्राफ्ट/इण्डियन पोस्टल आर्डर आदि कार्यालय में रोकड़	
	उपदान निधि			बैंक अतिशेष	
	अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पारिश्रमिक निक्षेप			(ख) ऋण और अग्रिम धन	
	प्रतिभूत निक्षेप			कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिम धन (भवन निर्माण सवारी गाड़ी की खरीद और अन्य समान अग्रिम धन)	
	अन्य निक्षेप (विनिर्दिष्ट करें)			(त्यौहार, बाढ़, यात्रा, वेतन, चिकित्सा, यात्रा छुट्टी रियायत और अन्य समान अग्रिम धन)	
	ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं			क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों के पास स्थायी अग्रिम धन (अग्रदाय, आवर्ती यात्रा भत्ता और अन्य ऐसे अग्रिम धन)	
	(ख) प्रावधान			प्रकीर्ण अग्रिम धन	
	पेंशन तथा अन्य समान कर्मचारी-लाभ-योजनाएं आनुषंगिकताएं			निक्षेप कार्यालय आवास के लिए मालिक के पास,	
	अन्य व्यवस्था (विनिर्दिष्ट करें)			––टेलीफोन प्राधिकारी के पास	
				डाक प्राधिकरण के पास	
				विद्युत प्राधिकारी के पास	
				अन्य निक्षेप (विनिर्दिष्ट किए जाएं)	
				पूर्व संदत्त खर्चे (किराया, रेट कर, शुल्क और बीमे की असमाप्त स्थिति)	

[सं० 3(56)/76-नि०नि०तथा नि० उ०]

New Delhi, the 30th September, 1978

S.O. 2865.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 namely :—

1. These rules may be called the Export (Quality Control and Inspection) Second Amendment Rules 1978.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.—

(a) for rule 16, the following rules shall be substituted, namely :—

"16. Audit of accounts.—(1) The Council shall maintain proper books of accounts in respect to all transactions for all sums of money received and expended and the matter in respect of which the receipt and expenditure take place, all sales and purchases, the assets and liabilities so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Council and its offices and to explain its transactions and prepare Income and Expenditure Account and Balance-sheet as prescribed by the Comptroller and Auditor-General of India set out in Forms III and IV respectively or as nearer thereto as the circumstances admit; and such Income Expenditure Account and Balance-sheet shall be signed on behalf of the Council by the Secretary and the Additional Director of the Council.

(2) All such accounts of the Council shall be subject to audit annually by the Chartered Accountants appointed by the Council with the approval of the Central Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Council.

(3) The Chartered Accountants appointed under sub-rules (2) shall have the rights and privileges and authority in connection with such audit as exercised, enjoyed and enforced by the Chartered Accountants in connection with the audit of accounts of similar other organisations and in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the offices of the Council.

(4) The accounts of the Council as certified by the Chartered Accountants in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament."

(b) After Form II, the following forms shall be inserted at the end namely :—Form III & IV.

FORM-III

[See Rule 16(1)]

EXPORT INSPECTION COUNCIL

Income and Expenditure Account for the year Endings.....

EXPENDITURE			INCOME		
Figures for the previous year (Rs.)	Particulars	Figures for the current year (Rs.)	Figures for the previous year (Rs.)	Particulars	Figures for current year (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. Establishment			1. Income other than Government Grant	
	To pay of officers			By application fee from candidates applied for various posts	
	To pay of staff			By fees for issuing certificate of Origin Under Generalised System of Perferences.	
	To Dearness Allowance			By Foreign Service Contributions received	
	To Other Allowances (CCA, HRA)			By Interest	
	To Travelling Allowance			By other Income (To be specified)	
	(a) Officers			By Miscellaneous.	
	(b) Staff				
	(c) Council and other Committee Members			2. Government Grant	
	To Medical Assistance			3. Grant from Marketing Development Received from Govt. to meet deficit for operation of various preshipment Inspection schemes operated by the Export Inspection Agencies.	
	To Assistance for Welfare to employees				
	To contribution towards leave salary and Pension or its equivalent for employees on deputation to the Council			4. Excess of Expenditure over Income carried over to Balance-sheet.	
	To Council's Contribution to Contributory Provident Fund				
	Other Establishment Charges (To be specified).				
	2. Other Charges				
	To Stationery				
	To Printing & Binding				
	To Postage & Telegram				
	To Rent for office accommodation				
	To Electricity charges				
	To Telephone				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	To Audit Fee				
	To Repairs and Renewals				
	To Advertisement for Recruitment				
	To Subscriptions & Membership Fees				
	To local conveyance charges				
	To Depreciation				
	To Other specified items of Expenditure				
	To Miscellaneous				
	To Publicity				
	To Marketing Development fund-Payment to Export Inspection Agencies to meet the deficit for operation of various preshipment inspection schemes				
	To Training programme abroad				
	To Training Programme for Trainees from abroad				
	To participation in Committees/Council/ other similar bodies abroad.				
	To participation in Trade fair/Delegation				
	To Certificate of Origin under Generalised system of preferences.				
	To Organisation of Seminars/conventions and such other activities.				
	To other specified Expenditure				
	Excess of Income over Expenditure carried over to Balance-sheet.				

FORM-IV

[See Rule-16(1)]

EXPORT INSPECTION COUNCIL

Balance Sheet as at.....

Figures for the previous year (Rs.)	LIABILITIES	Figures for the current year (Rs.)	Figures for the previous year (Rs.)	ASSETS	Figures for the current year (Rs.)
1	2	3	4	5	6
	1. CAPITAL ACCOUNT			1. FIXED ASSETS	
	(Balance of the Excess of Income over Expenditure or vice-versa transferred from the Income & Expenditure Account).			(Distinguishing as far as possible between expenditure upon all items).	
	2. RESERVES AND SURPLUS			2. INVESTMENT	
	(To be specified if so created)			3. CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	
	3. SECURED LOANS			(A) Current Assets	
	4. UNSECURED LOANS			Interest Accrued on Investments	
	5. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			Stock and Stores	
	(A) Current Liabilities			Sundry Debtors	
	Salary & other personal claims payable to employees.			Cheques/Drafts/IPOS etc. in transit	
	Contributory Provident Fund			Cash in office	
	Gratuity Fund			Bank balances	
				(B) Loans and Advances	
				Interest bearing Advances to Employees (House Building, Purchase of Conveyance and other similar advances)	
				Interest Free Advances to Employees	

1	2	3	4	5	6
	Addl. D.A. & Wage Deposits Security Deposits • Other Deposits (To be specified). Interest accrued but not due on loans (B) PROVISIONS Pension and other similar employees benefit schemes Contingencies Other Provisions (To be specified).			(Festival, Flood, Travelling, Pay, Medical, LTC and other similar advances) Permanent Advance with Regl./Sub-offices (Imprest, Revolving TA and other such advances). Misc. Advances Deposit with—Land-lord for office accommodation —Telephone Authority —Postal Authority —Electricity Authority Other Deposit (To be specified) Pre-paid Expenses (Unexpired position of rent, rates, Taxes, duties and Insurance)	

[F. No. 3(56)/76-EI&EP]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

का० आ० 2866.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ढलवां लोहे की स्वाएल पाइपों तथा फिटिंग का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ढलवां लोहे की स्वाएल पाइपों और फिटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम ढलवां लोहे की स्वाएल पाइपों तथा फिटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ढलवां लोहे की स्वाएल पाइपों तथा फिटिंगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970 में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6 निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन निर्यातकर्ता, प्रत्येक परेषण के लिए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से फीस जो कम से कम दस रुपए होगी, निरीक्षण फीस के रूप में अभिकरण को देगा।"

[सं० 6(9) 76-नि० नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 30th September, 1978

S.O. 2866.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the Export of Cast Iron Soil Pipes and Fittings (Inspection) Amendment Rules, 1976, the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Export of Cast Iron Soil Pipes and Fittings (Inspection) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Cast Iron Soil Pipes and Fittings (Inspection) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the export of Cast Iron Soil Pipes and Fittings (Inspection) Rules, 1970, for rule 6 the following shall be substituted, namely :—

"6. Inspection fee : Subject to a minimum of rupees ten a fee at the rate of 0.5 per cent of the free on board value of each consignment shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules."

[No. 6(9)/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1978

का०आ० 2867.—सर्वश्री हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पूना 411018 को 17,88,000/- रुपये (केवल सत्रह लाख अठासी हजार रुपये) का एक आयात लाइसेंस सं० आई/डी/1077291/सी/एक्स एक्स/एच/64/77 दिनांक 7-9-77 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति बम्बई सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत थी एवं उसका आंशिक उपयोग किया गया था। यह 2,30,452 रुपये तक प्रयुक्त हो गई थी और इसमें 15,57,548 रुपये शेष थे।

2. इस तर्क के समर्थन में प्रार्थी ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तद्नुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 के उपखण्ड 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पूना को जारी किये गये लाइसेंस सं० आई/डी/1077291 दिनांक 7-9-77 की उक्त मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति लाइसेंसधारी को अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या एच ए बी/2/77-78/पी आई एस ए]

मोहन लाल भार्गव, उप-मुख्य नियंत्रक

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 10th August, 1978

S.O. 2867.—M/s. Hindustan Antibiotics Ltd., Poona-411018 were granted an import licence No. I/D/1077291/C/XX/H/64/77 dated 7-9-1977 for Rs: 17,88,000 (Rupees Seventeen Lakhs and Eighty Eight Thousands only). They

have applied for the issue of a duplicate Customs proposes copy of the said licence on the ground that the original Customs Purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Customs Purposes copy was registered with the Customs authorities at Bombay, utilised partly. It was utilised for Rs. 2,30,452 and the balance available on it was Rs. 15,57,548.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Subclause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy of licence No. I/D/1077291 dated 7-9-1977 issued to M/s. Hindustan Antibiotics Ltd., Poona is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. HAB/2/77-78/PISA]
MOHAN LAL BHARGAVA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

का० आ० 2868.—सर्वश्री आगरा रोलर फ्लोर मिल्स, बेलनगंज, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा यह सूचना दी गई है कि गेहूं के उत्पादों के विनिर्माण के लिए फ्लोर मिल मशीनरी के लिए आपातकालीन फालतू पुर्जों के आयात के लिए 40,000 रुपए (चालीस हजार रुपए मात्र) का जो आयात लाइसेंस सं० पी/डी/2210216/सी/एक्स एक्स/65/एच/77 दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 जारी किया गया था उसकी सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति नई दिल्ली, सीमा-शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत करवाने के बाद और 16066.52 रुपए (सोलह हजार छियासठ रुपये बावन पैसे मात्र) के लिए आंशिक रूप से उपयोग करने के बाद अस्थानस्थ हो गयी/खो गयी है।

2. इस तर्क के समर्थन में सर्वश्री आगरा रोलर फ्लोर मिल्स, बेलनगंज, आगरा ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है और निदेश देता है कि उन्हें उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रति जारी की जाए। मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन, प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. विषयाधीन लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० फ्लोर/43(1)/77-78/आर० एम० 5]
सी० एस० आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 2868.—It has been reported by M/s. Agra Roller Flour Mills, Belanganj, Agra (U.P.) that Customs Purposes copy of Import Licence No. P|D|2210216|C|XX|65|H|77 dated 14th October, 1977 granted to them for a value of Rs. 40,000 only (Rupees Forty thousand only) for import of Emergency spares for the Flour Mill machinery for the manufacture of wheat products has been misplaced/lost after having been registered with New Delhi-Custom's House and it has been utilised partly for Rs. 16066-52 paise (Rs. sixteen thousand and sixty-six and fifty-two paise only).

2. In support of this contention M/s. Agra Roller Flour Mills, Belanganj, Agra have given an affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of the licence in question has been misplaced/lost and directs that a duplicate Customs Purposes copy of the above mentioned Import licence should be issued to them. The original Customs purposes copy is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the licence in question is being issued separately.

[No. Flour/43(1)/77-78/R.M. 5]
C. S. ARYA, Dy. Chief Controller

लाइसेंस रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर 1978

का० आ० 2869.—सर्वश्री भारतीय शूगर एण्ड जनरल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, सहारनपुर, पिप्ली रोड, यमुना नगर-135001 को संलग्न सूची के अनुसार आई०डी० ए० क्रेडिट से कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिये 13,61,637- रुपए का एक आयात लाइसेंस संख्या-पी०/डी०/2206303/आर/आईएन/61/एच/43-44/आरएम-4, दिनांक, 14-12-76 प्रदान किया गया था।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा पंजीकृत कराये जाने के पश्चात् खो/अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति में 9,32,207 रुपए का उपयोग करना शेष था।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस संख्या-पी/डी/2206303, दिनांक 14-12-76 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ गई है तथा इसलिये निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जाये। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मिसिल संख्या-मश/आई-2(2)एएम-77 आरएम-4/2377]
सी०एस० आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक, कृते मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2869.—M/s. Indian Sugar & General Engg. Corpn., Saharanpur, Pipli Road, Yamunanagar-135001 were granted import licence No. P/D/2206303/R/IN 61 H 43-44 RM-4 dt. 14-12-1976 for import of raw materials and components as per list attached to it valued at Rs. 13,61,637 from IDA Credit.

2. They have requested for the issue of duplicate Exchange Control Copy of the above said licence on the ground that the original exchange control copy has been lost or misplaced after having been registered with the Customs, Calcutta. It has been further reported by the licencee that the exchange control copy had an un-utilized balance of Rs. 9,32,207 only.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original exchange control copy of import licence No. P|D|2206303 dt. 14-12-76 has been lost or misplaced and hence directs that a duplicate exchange Control Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy is hereby cancelled.

4. The Duplicate Exchange Control Copy of the said licence is being issued separately.

[File No. Mach/I-2(2)/AM-77/RM-IV/2377]
C. S. ARYA, Dy. Chief Controller for Chief Controller
for Chief Controller

आदेश

का० आ० 2870. सर्वश्री पोलीनिट प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को 7,60,409 रुपए (केवल सात लाख साठ हजार चार सौ नौ रुपए) ($83645) का एक आयात लाइसेंस संख्या पी/सीजी/1418617/एस/आईएन/59/एच/27-28/सीजी-3, दिनांक, 20-5-1976 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की एक अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण

प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त आयात लाइसेंस सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं था। यह प्रयुक्त नहीं हुआ था और इसमें 7,60,409 रुपए की धन राशि शेष थी।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने पंजीयक और महानगरीय जिला-धीश, बम्बई के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। इसलिए, यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप-खण्ड-9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री पोलीनिट प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को जारी किए गए लाइसेंस संख्या-पी/सीजी/1418617, दिनांक, 20-5-1976 की उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं।

3. लाइसेंसधारी की उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मिसिल संख्या-सीजी-3/21/(93)/70-71]

जी० एस० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 2870.—M/s. Polynit Pvt. Ltd., Bombay were granted import licence No. P/CG/1418617/S/IN/59/H/27-28/CGIII dated 20-5-1976 for Rs. 7,60,409 (Rupees Seven Lakhs sixty thousand four hundred and nine only) (US $83645). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control purposes Copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been lost/misplaced. It is further stated that the import licence, referred to above was not registered with the Customs authority. It was not utilised and the balance available on it was Rs. 7,60,409.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit duly sworn before the Registrar and Metropolitan Magistrate, Bombay. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the power conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Exchange Control Purposes Copy of licence No. P/CG/1418617 dated 20-5-76 issued to M/s. Polynit Pvt. Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes Copy of the said licence is being issued separately to the licencee.

[File No. CG. III/21(93)/70-71]
G. S. GREWAL, Dy. Chief Controller

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1978

का० आ० 2871.—व्यापार और वाणिज्यिक चिह्न नियम, 1959 के नियम 157 के उप नियम (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि श्री आर० रामालिंगम, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता (रजिस्ट्रेशन संख्या-33) के कारोबार के मुख्य स्थान का पता व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में जैसा नीचे दिखाया गया, परिवर्तित किया गया है :—

"आर० रामालिंगम, बी० ए०,
238, रंगिया गौडर स्ट्रीट,
कोयम्बतूर-641001"

[मि० सं० 29(1)/आई० टी०/टी० एम०/78]

वी० श्रीनिवासन, उप सचिव

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 11th August, 1978

S.O. 2871.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 157 of the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 it is hereby notified that the addre s of the principal place of business of Shri R. Ramalingam, a Registered Trade Marks Agent (Registration No. 33) has been altered in the Register of Trade Marks Agents as shown below :—

"R. Ramalingam, B.A.,
238, Rangiah Gowder Street,
Coimbatore-641001".

[F. No. 29(1)-IT/TM/78]
V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का०आ० 2872.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ (उ०प्र०)।
3. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद (उ०प्र०)।

[सं० ई-14015(6)/77-हिन्दी]

ह० ल० अहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2872.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Offices the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi.
2. Scooters India Ltd., Lucknow (U.P.).
3. Triveni Structurals Ltd., Naini, Allahabad (U.P.).

[No. E-14015(6)/77-Hindi]
H. L. AHUJA, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

का० आ० 2873.—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० पी० परमेश्वरन्, आयुक्त (औद्योगिक सहकारिता), औद्योगिक विकास विभाग, को तत्काल से अन्य आदेश होने तक कयर बोर्ड, एर्णाकुलम का पदेन अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० 15(46) 78-आई०सी० सी०]

एस० जे० कोयलो, संयुक्त सचिव

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 2873.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the Central Government hereby appoints Shri A. P. Parameshwaran, Commissioner (I.C.), Department of Industrial Development, as ex-officio Chairman, Coir Board, Ernakulum, with immediate effect, until further orders.

[No. 15/46/78-ICC]
S. J. COELHO, Jt. Secy.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 1978-09-13

का० आ० 2874 समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसार अनुसूचित किया जाता है कि जिस भारतीय मानक का ब्यौरा नीचे दिया गया है वह रद्द कर दिया गया है और अब वापस माना जाये ।

अनुसूची

क्रम संख्या	भारतीय मानक की संख्या और रद्द होने की तिथि	भारतीय मानक के राजपत्र में छपने की तिथि और एस ओ संख्या	विवरण
1.	I S : 1465–1964 प्लास्टिक बटन (तापस्थापी) की परीक्षण पद्धतियां (पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-04-09 में एस ओ 1081 दिनांक 1966-03-25 के अन्तर्गत प्रकाशित ।	IS : 8543 (भाग 13/खण्ड I) 1966 प्लास्टिक की परीक्षण पद्धतियां भाग-13, विशिष्ट उत्पादों के परीक्षण, खण्ड-1—प्लास्टिक बटनों (तापस्थापी) की जानकी लेने और परीक्षण पद्धतियों के प्रकाशन के फलस्वरूप रद्द ।

[संख्या सी एम डी/13 : 7]

DEPT. OF CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Indian Standards Institution)

New Delhi, 1978-09-13

S.O. 2878.—In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard, particulars of which is/mentioned in the Schedule given herein after, has been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1.	IS : 1465-1964 Methods of test for plastic buttons (thermosetting) (revised)	S.O. 1081 dated 1966-03-25 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-04-09.	Consequent upon the publication IS : 8543 (Pt XIII/Sec. 1)-1968 Methods of testing plastics : Part XIII Tests for specific products, Section 1—Methods for sampling and tests for plastics buttons (thermosetting).

[No. CMD/13 :7]

का० आ० 2875—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किये हैं जिसकी डिजाइन और णाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दिया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिन्ह प्रत्येक के आगे दी गई तिथि से लागू होंगी ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और इकाई	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
1.	I S : 5996	पट्टे की सूती डक	I S : 5996-1970 पट्टे की सूती डक की विशिष्टि ।	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें I S I शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है और उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या दी गई है ।	1977-02-16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	IS : 7466	प्रेशर कुकर के लिये रबड़ गैस्केट	IS : 7466—1974 प्रेशर कुकर के रबड़ गैस्केट की विशिष्टि ।	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।	1978-06-01

[सं० सी एम डी/13 : 9]

S.O. 2875.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark(s) design(s) of which together with the verbal description of the design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) are given in the Schedule hereto annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of effect
1.		Cotton belting ducks	IS : 5996-1970 Specification for cotton belting ducks	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1977-02-16
2.		Rubber gasket for pressure cookers	IS : 7466-1974 Specification for rubber gasket for pressure cookers	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1978-06-01

[No. CMD/13 :9]

का० आ० 2876:—भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1970-05-30 में प्रकाशित तत्कालीन औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार एवं कम्पनी मामलों (औद्योगिक विकास विभाग) मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस ओ 1907 दिनांक 1970-04-22 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कपड़े धोने के साबुन की मानक चिन्ह में कुछ परिवर्तन किया गया है । परिवर्तित मानक चिन्हों की डिजाइन तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्षक और शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियम तथा विनियम के निमित्त यह मानक चिन्ह 1978-08-01 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मारक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1.	IS : 285	कपड़े धोने का साबुन	IS : 285—1974 कपड़े धोने के साबुन की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद-संख्या और नीचे की ओर शब्द 'बिल्ट सोप' और 'प्योर सोप' दिये गये हैं ।
2.				

(संख्या सी एम डी/13:9)

S.O. 2876.—In supersession of the then Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs (Department of Industrial Development) (Indian Standards Institution) notification number S.O. 1907 dated 1970-04-22, published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1970-05-30, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Marks for laundry soaps have been revised. The revised designs of the Standard Marks together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the designs are given in the following Schedule.

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-08-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.		Laundry soaps	IS : 285-1974 Specification for laundry soaps (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'BUILT SOAPS' and 'PURE SOAPS' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the designs.
2.				

[No. CMD/13 :9]

का०आ० 2877.— भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है । यह फीस प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस	लागू होने की तिथि
1.	पट्टे की सूती डक	I S : 5996—1970 पट्टे की सूती डक की विशिष्टि	एक मीटरी टन	(1) पहली 500 इकाइयों के लिये रु० 10.00 प्रति इकाई ; (2) 501 से 1000 तक की इकाइयों के लिये रु० 5.00 प्रति इकाई; और (3) 1001वीं और उससे ऊपर की इकाइयों के लिये रु० 2.00 प्रति इकाई ।	1977-02-16
2.	प्रेशर कुकर के रबड़ गैस्केट	I S : 7466—1974 प्रैशर कुकर के लिये रबड़ गैस्केट की विशिष्टि ।	एक गैस्केट	5 पैसे	1978-06-01

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 10]

S.O. 2877.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for various products details of which are given in the Schedule hereto annexed, have been determined and the fee(s) shall come into force with effect from the dates shown against each :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit	Date of Effect
1.	Cotton belting ducks	IS : 5996-1970 Specification for cotton belting ducks	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501 to 1000 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1001 unit and above.	1977-02-16
2.	Rubber gasket for pressure cookers	IS : 7466-1974 Specification for rubber gasket for pressure cookers	One Gasket	5 Paise	1978-06-01

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 1978—09—14

का० आ० 2878.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिन्ह निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दिया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिन्ह 1978-06-16 से लागू होगा :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और इकाई	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		टोक्साफीन धूलन पाउडर	IS : 7947—1976 टोक्साफीम धूलन पाउडर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है, उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है ।

[संख्या सी एम डी/13 : 9]

New Delhi, 1978—09—14

S.O.2878.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-06-16 :

THE SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Toxaphene dusting powders	IS : 7947-1976 Specification for toxaphene dusting powders	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 2879.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने एक मानक चिन्ह निर्धारित किया है जिसकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तथा भारतीय मानक के शीर्षक सहित अनुसूची में दिया गया है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित यह मानक चिन्ह दिनांक 1978-01-01 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		तीन पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट	IS : 1293—1967 तीन पिन प्लग और साकेट आउटलेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।

[संख्या सी एम डी/13 : 9]

S.O. 2879.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-01-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
1	2	3	4	5
1.	IS:1293 ISI	Three-pin plugs and socket-outlets	IS : 1293-1967 Specification for three-pin plugs and socket-outlets (first revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 2880.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि टोक्साफीन धूलन पाउडर की प्रति इकाई की मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है । यह फीस दिनांक 1978-06-16 से लागू होगी:

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1	2	3	4	5
1.	टोक्साफीन धूलन पाउडर	IS : 7947—टोक्साफीन धूलन पाउडर की विशिष्टि ।	एक मीटरी टन	रु० 5.00

[संख्या सी एम डी/13 : 10]

S.O. 2880.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for toxaphene D.P. details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1978-06-16 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	5
1.	Toxaphene dusting powders	IS : 7947-1976 Specification for toxaphene dusting powders	One Tonne	Rs. 5.00

[No. CMD/13 : 10]

का०आ० 2881.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (2) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि तीन पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिये गये ब्यौरों के अनुसार निर्धारित की गई है । यह फीस दिनांक 1978-01-01 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्संबंधी मानक की संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1	2	3	4	5
1.	तीन पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट	IS : 1293-1967 तीन पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	100 नग	50 पैसे

[संख्या सी/एम डी/13 : 10]

वाई० एस० वेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

S.O. 2881 .—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee per unit for three-pin plugs & socket outlets details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1978-01-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1	2	3	4	5
1.	Three-pin plugs and socket-outlets	IS : 1293-1967 Specification for three-pin plugs and socket-outlets (first revision)	100 Pieces	50 paise

[No. CMD/13 : 10]

Y. S. VENKATESWARAN, Additional Director General

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1978

का०आ० 2882.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, सलाया-मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मोरवी हाउस, जामनगर रोड, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

तालुका : पालनपुर जिला : बनासकान्था गुजरात : राज्य

ग्राम	खसरा नं०	सीमा		
		एच०	ए०	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
खेमाणा	123	0	13	60
	121	0	18	00
	32	0	12	80
	33/1	0	08	16
	33/2	0	07	20
	33 3	0	02	00
	43/3	0	04	64
	43/2	0	04	32
	43/1	0	06	00
	44/5	0	12	00
	44/2	0	06	00
	54+55	0	18	56
	48	0	12	48
	20+47+49	0	14	00
	50+51/पी	0	02	00
	52+53	0	52	80
मलाना	153	0	22	40
	154/2	0	01	52
	154/1	0	09	12
	145	0	09	00

[सं० 12020/6/76-ओ०]

एस०एम०बाई० नदीम, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 17th September, 1978

S.O. 2882.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the Purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "Morvi House" Jamnagar road Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Palanpur District : Banaskantha Gujarat State

Village	Survey No.	Extent H.	A.	Sq. M
Khemana	123	0	13	60
	121	0	18	00
	32	0	12	80
	33/1	0	08	16
	33/2	0	07	20
	33/3	0	02	00
	43/3	0	04	64
	43/2	0	04	32
	43/1	0	06	00
	44/5	0	12	00
	44/2	0	06	00
	54+55	0	18	56
	48	0	12	48
	20+47+49	0	14	00
	50+51/P	0	02	00
	52+53	0	52	80
Malana	153	0	22	40
	154/2	0	01	52
	154/1	0	09	12
	145	0	09	00

[No. 12020/6/76-Prod.]
S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का०आ० 2883.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने 14 मार्च, 1978 से डा० पी०एस०आर० के० हरनाथ, प्रधानाचार्य, कुरनूल मेडिकल कालेज, कुरनूल को भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना एस० ओ० संख्या 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 14 और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"14. डा० पी० एस० आर० के० हरनाथ,
प्रधानाचार्य,
कुरनूल मेडिकल कालेज,
कुरनूल ।"

[संख्या वी० 11013/1/78-एम ई (पी)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2883.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. P. S. R. K. Harnath, Principal, Kurnool Medical College, Kurnool, has been elected by the Sri Venkateswara University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 14th March, 1978 :—

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the late Ministry of Health S.O. No. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", for serial No. 14 and entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"14. Dr. P. S. R. K. Harnath,
Principal,
Kurnool Medical College,
Kurnool."

[No. V. 11013/1/78-M.E. (Policy)]

का०आ० 2884.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने 18 जुलाई, 1978 से डा० पी० एम० डारक, परामर्शदाता शल्य चिकित्सक एवं मूत्र विज्ञानी, कैन्टोनमेंट, औरंगाबाद को भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना एस०ओ० संख्या 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 23 और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"23. डा० पी० एम० डारक,
परामर्शदाता शल्य चिकित्सक एवं मूत्र विज्ञानी,
कैन्टोनमेंट,
औरंगाबाद ।"

[संख्या वी० 11013/1/78-एम ई(पी)]

S.O. 2884.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. P. M. Darak, Consulting Surgeon and Urologist, Cantonment, Aurangabad, has been elected by the Maharashtra University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 18th July, 1978 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the late Ministry of Health S.O. No. 138 dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3" for serial No. 23 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"23. Dr. P. M. Darak,
Consulting Surgeon and Urologist,
Cantonment, Aurangabad".

[No. V. 11013/1/78-M.E. (Policy)]

का०आ० 2885.—यतः केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 7 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (क) के अनुसरण में

और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करके डा० बी०बी० गेटोन्डे, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, बम्बई को 30 जून, 1978 से भारतीय चिकित्सा परिषद का सदस्य मनोनीत किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना एस० ओ० संख्या 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उप-धारा 1 के खण्ड (क) के अधीन मनोनीत" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 5 और उससे संबन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"5. डा० बी० बी० गेटोन्डे,
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान,
बम्बई।

[संख्या बी० 11013/1/78-एम०ई०(पी)]
आर० वी० श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 2885.—Whereas the Central Government in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the Government of Maharashtra, have nominated Dr. B. B. Gaitonde, Director of Medical Education and Research, Bombay, to be a member of the Medical Council of India with effect from the 30th June, 1978 :—

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (I) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (I) of section 3," for serial No. 5 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely :—

"5. Dr. B. B. Gaitonde,
Director of Medical Education,
and Research, Bombay."

[No. V. 11013/I/78-M.E.(Policy)]
R. V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1978

का०आ० 2886.—वायुयान (जन स्वास्थ्य) नियमावली, 1954 के नियम 67 के उपनियम (2) और भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम, 1955 के नियम 89 के उपनियम (2) के अनुसरण में तथा इस संबंध में भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 7 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या 29-10/64-आई० एच०एफ० का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत में विमान पत्तन अथवा समुद्र पत्तन के पीतज्वर पृथक अस्पताल में संगरोधन के लिये निरुद्ध यात्रियों को अथवा कार्मिक टोली के किसी कार्मिक को उसकी निरुद्ध अवधि के दौरान आहार सहित प्रदान की गई सेवाओं के उपलक्ष में जो शुल्क लिये जायेंगे वे इसके साथ संलग्न सूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार होंगे। तथापि संगरोधन व्यक्ति को उसके रुकने की अवधि के दौरान दिये गए किसी भी उपचार और औषधि के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगी।

अनुसूची

(क) संगरोधन के वास्तविक समय से निरुद्ध अवधि के हर 24 घंटे के लिये प्रति वयस्क (3 वर्ष से अधिक) के लिए 55/- रु० और तीन वर्ष तक के बालकों के लिए प्रति बालक 25/- रुपये :

परन्तु छुट्टी मिलने के दिन यदि ठहरने की अवधि 12 घंटे से अधिक न हो तो उस दिन को प्रत्येक 4 घंटे या उसके किसी अंश के लिये 3 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रति बालक 6/- रुपए और अन्य व्यक्तियों के लिए 14/- रुपये शुल्क होगा।

(ख) वातानुकूल की सुविधाएं उपलब्ध करने के मामलों में संगरोधन के वास्तविक समय से 24 घंटे के लिए प्रति व्यक्ति 15/- रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, परन्तु छुट्टी मिलने के दिन ठहरने की अवधि 12 घंटे से अधिक न हो तो उस दिन प्रत्येक चार घंटे या उसके किसी अंश के लिये 4/- रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त खर्च लिया जाएगा,

(ग) यदि यात्रियों और कार्मिक दल के सदस्यों का संगरोधन समुद्र पत्तन से विमान पत्तन स्थित पीतज्वर पृथक अस्पताल में अथवा विमान पत्तन से समुद्र पत्तन स्थित पीतज्वर पृथक अस्पताल में किया जाएगा तो संगरोधन वाले व्यक्ति का यातायात संबंधी खर्च अलग से लिया जाएगा। जो वास्तविक खर्च तक सीमित होगा।

[सं० ओ० 12020/4/74-आई० एच०]
एस० पी० गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2886.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 67 of the Aircraft (Public Health) Rules, 1954 and of sub-rule (2) of rule 89 of the Indian Port Health Rules, 1955 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 29-10/64-IHF, dated the 7th April, 1965, the Central Government hereby notifies that the charges to be levied on account of services inclusive of food rendered in respect of passengers or a member of the crew detained in quarantine in Yellow Fever Isolation Hospital at airport or seaport in India during the period of his detention shall be as specified in the Schedule hereto annexed. No charge shall, however, be levied for any medical treatment or drugs that the quarantined person may be given during the period of his detention.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

(a) Rs. 55/- per head for adult (above 3 years) and Rs. 25/- per head for children upto 3 years for every 24 hours of detention counting from the actual time of quarantine :

Provided that if on the day of discharge the stay does not exceed 12 hours, the charges shall be Rs. 6/- per head for children upto 3 years and Rs. 14/- per head for others, in respect of that day for every 4 hours or part thereof;

(b) In cases where air-conditioning services are provided, additional charge of Rs. 15/- per head for 24 hours counting from the actual time of quarantine, shall be levied :

Provided that if on the day of discharge the stay does not exceed 12 hours, such additional charges shall be Rs. 4/- per head in respect of that day for every 4 hours or part thereof;

(c) if the passengers and members of the crew from the sea-ports are quarantined in Yellow Fever Isolation Hospitals at the Airports or vice-versa the charges for transportation of quarantined person shall be levied extra, limited to actual cost.

[No. O. 12020/4/74-IH]
S. P. GOSWAMI, Under Secy

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का०आ० 2887.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग की

अधिसूचना सं० का०आ० 4315, तारीख 26 अक्तूबर, 1976 द्वारा उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 437.00 एकड़ (लगभग) या 177.05 हेक्टर (लगभग) क्षेत्रफल वाली भूमियों में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियों में से 342.23 एकड़ (लगभग) या 138.50 हेक्टर (लगभग) में कोयला पाया जा सकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची "क" में वर्णित 342.23 एकड़ (लगभग) या 138.50 हेक्टर (लगभग) माप की भूमियों में खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खुदाई और उनकी तलाश करने, उनका अन्वेषण करने, उन पर कार्य करने और उन्हें लेने के अधिकार अर्जित करने के, अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण :

(1) इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के रेखांक का निरीक्षण कलक्टर बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या मुख्य खनन इंजीनियर (निर्माण और विकास) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सैंक्टोरिया, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था है—

8(1). कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि में हितबद्ध है, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना के जारी होने के तीस दिन के भीतर, समस्त भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों के अर्जित किए जाने पर आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना कि वह स्वयं कोयले के उत्पादन के लिए भूमि में खनन संक्रिया करना चाहता है और यह कि ऐसी संक्रिया, केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आक्षेप नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को, या तो व्यक्तिगत रूप में या विधिक व्यवसायी द्वारा, सुने जाने का अवसर देगा तथा ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, केन्द्रीय सरकार को ऐसी भूमि की बाबत, जो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित की गई है या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों की बाबत या तो एक रिपोर्ट देगा या ऐसी भूमि के विभिन्न पार्सलों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों की बाबत विभिन्न रिपोर्ट देगा, जिसमें उस सरकार के विनिश्चय के लिए, उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित आक्षेपों पर उसकी सिफारिशें होंगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो भूमि को या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाने पर प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा।

टिप्पणी: (3) कोयला नियंत्रक, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उक्त सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनुसूची "क"

छोटोढेमुआ-गंगुटिया मौजा

राणीगंज कोयला-क्षेत्र

ब्लाक—"क"

हा०सं० 33/1886

तारीख 14 अप्रैल, 1978

(जिसमें ऐसी भूमि दर्शित की गई है जिसमें खनिजों के खनन, खदान, वेधन, खोदाई और तलाश, अन्वेषण उन पर कार्य करने और उन्हें लेने के अधिकार अर्जित किए जाने हैं)

खनन अधिकार :

क्रम सं०	मौजा (ग्राम)	थाना संख्या	पुलिस थाना	जिला	क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणियां
1.	गंगुटिया	28	कुल्टी	बर्दवान	163.56	भाग
2.	छोटोढेमुआ	42	,,	,,	178.67	भाग
			कुल क्षेत्र :		342.23 एकड़ (लगभग)	
			या		138.50 हेक्टर (लगभग)	

सीमा-वर्णन :

क—ख . रेखा, मौजा गंगुटिया में से (पूर्व-पश्चिम) होकर गुजरती है और सीदेपुर कोलियरी की वर्तमान खनन पट्टा सीमा पर बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ग . रेखा, मौजा गंगुटिया, जो कि सीदेपुर कोलियरी का खनन पट्टान सीमा भी है, की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—घ . रेखा, मौजा छोटा डेमुआ, जो कि सीदेपुर कोलियरी की खनन पट्टा सीमा भी है, की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिंदु "घ" पर मिलती है।

घ—ङ . रेखा, मौजा छोटा डेमुआ में से होकर, सीदेपुर कोलियरी की खनन पट्टा सीमा के साथ साथ जाती है और सीदेपुर कोलियरी की विद्यमान पट्टा सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ—च . रेखा, मौजा छोटा डेमुआ की पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और छोटा डेमुआ, गंगुटिया और दिशेरगढ़ मौजा के त्रिसन्धिस्थल बिन्दु "च" पर मिलती है।

च—छ . रेखा मौजा गंगुटिया और दिशेरगढ़ के बीच सामान्य सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ—क . रेखा, मौजा गंगुटिया की पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19(6)/78-सी०एल०]

एस०आर० ए० रिजवी, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2887.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S. O. 4315, dated the 26th October, 1976, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 437.43 acres (approximately) or 177.05 hectares (approximately) of lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the lands measuring 342.23 acres (approximately) or 138.50 hectares (approximately) out of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 342.23 acres (approximately) or 138.50 hectares (approximately) described in Schedule appended hereto.

Note 1.—The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Burdwan (West Bengal) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Chief Mining Engineer (Construction and Development), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan (West Bengal).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provision of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows :

8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or made different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

CHHOTODHEMUA—GANGUTIA MOUZA

RANIGANJ COALFIELD

BLOCK—'A'

Drawing No. 33/1886
Dated 14/4/1978
(Showing lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are to be acquired).

Mining Rights

Sl. No.	Mouza (Village)	Thana Number	Police Station (Thana)	District	Area in acres	Remarks
1.	Gangutia	28	Kulti	Burdwan	163.56	Part
2.	Ghhota Dhemua	42	Kulti	—do—	178.67	Part

Total Area—342.23 acres (Approximately)
or 138.50 hectares (Approximately)

BOUNDARY DESCRIPTION:

A—B —Line passes through Mouza Gangutia (East-West) and meets at point 'B' on the existing mining lease boundary of Sodepur Colliery.

B—C —Line passes along the Eastern boundary of Mouza Gangutia, which is also the mining lease boundary of Sodepur Colliery and meets at point 'C'.

C—D	—Line passes along the Eastern boundary of Mouja Chhota Dhemua which is also the mining lease boundary of Sodepur Colliery and meets at point 'D'.
D—E	—Line passes through Mouza Chhota Dhemua along mining lease boundaryof Sodepur Colliery and meets at point 'E' on the existing lease boundary of Sodepur Colliery.
E—F	—Line passes along the Western boundary of Mouza Chhota Dhemua and meets at point 'F' at the tri-junction point of Chhota Dhemua, Gangutia and Dishergarh Mouzas.
F—G	—Line follows the common boundary between Gangutia and Dishergarh Mouzas and meets at point 'G'.
G—A	—Line passes along the Western boundary of Mouza Gangutia and meets the starting point—'A'.

[No. 19 (6)/78-CL]
S. R. A. Rizvi, Director

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1978

का० आ० 2888.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० 2392 तारीख 15 जुलाई, 1977 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के अर्जन के आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 0.30 एकड़ (लगभग) या 0.12 हेक्टेयर (लगभग) भूमि अर्जित की जानी चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घोषित करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 0.30 एकड़ (लगभग) या 0.12 हेक्टेयर (लगभग) भूमि अर्जित की जाती है ।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण, उपायुक्त, गिरिडिह (बिहार) के कार्यालय में, या कोयला नियंत्रक, 1 कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रेवेन्यू सेक्शन) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

धोबीडिह जटकुटी ब्लाक

(गिरिडिह कोयला क्षेत्र)

रेखांक सं० रेव/47/77

तारीख 14 सितम्बर, 1977

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	प्लाट	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	धोबीडिह	गिरिडिह	193	गिरिडिह	119	0.10	आंशिक
2.	कुरहुर-बारी	गिरिडिह	194	गिरिडिह	2132	0.20	आंशिक

कुल क्षेत्रफल : 0.30 एकड़ (लगभग)
या 0.12 हेक्टेयर (लगभग)

ग्राम धोबीडिह में अर्जित किए गए प्लाट की संख्या :—119

ग्राम कुरहुरबारी में अर्जित किए गए प्लाट की संख्या :—2132

सीमा वर्णन

प्लाट सं० 119-ग्राम धोबीडिह में, उत्तर में प्लाट सं० 112, दक्षिण में रेलवे लाइन से, पूर्व में प्लाट सं० 117 और 118 से, पश्चिम में प्लाट सं० 120 से घिरा हुआ है।

प्लाट सं० 2132—ग्राम कुरहुरबारी में उत्तर और पश्चिम में प्लाट सं० 2133 से, पूर्व में प्लाट सं० 2118 और दक्षिण में रेलवे लाइन से घिरा हुआ है ।

[सं० 19(72)/77-सी० एल०]

New Delhi, the 16th September, 1978

S.O. 2888.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2392 dated the 15th July, 1977, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification ;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government ;

And Whereas the Central Government after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 0.30 acre (approx.) or 0.12 hectare (approx.) described in the schedule appended hereto should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 0.30 acre (approx.) or 0.12 hectare (approx.) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspeficted in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar), or in the Office of he Coal Controller, I, Council House Street, Calcutta, or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

DHOBIDIH-JATKUTI BLOCK

(Giridih Coalfield)

Drg. No. Rev/47/77
Dated 14-9-1977
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	Thana No.	District	Plot No.	Area	Remarks
1.	Dhotidi	193	Giridih	119	10	part
2.	Kurhurbaree	194	,,	2132	0.20	,,

Total area : 0.30 acre (approximately)
or 0.12 hec. (Approximately)

Plot no. acquired in village Dhobidih :—

119.

Plot no. acquired in village Kurhurbaree :—

2132.

Boundary Description—

Plot no. 119 surrounded on North by plot no. 112 on South by railway line on East by plot nos. 117 & 118 on West by Plot no. 120 in village Dhobidih.

Plot no. 2132 surrounded on North & West by plot no. 2133, on East by plot no. 2118 and on South by railway line and in village Kurhurbaree.

[No. 19(72)/77-CL]

शुद्धि पत्र

का० आ० 2889.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 25 मार्च, 1978 के पृष्ठ 913 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 844 तारीख 9 मार्च, 1978 में,—

1. "राजगमर"—शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आया है, "राजगमार" शब्द पढ़ें।

2. अनुसूची में, ग्राम "राजगमार" के सामने तहसील स्तम्भ के नीचे "काटघोरा" के स्थान पर "कटघोरा" पढ़ें।

[सं० 19(63)/77 सी एल]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

CORRIGENDUM

S.O. 2889.—In the notification of Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 844, dated the 9th March, 1978, published at pages 913-914 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th March, 1978—

At page 914, under the heading Boundary Description, in line A-B for S.O. No. 9.

Read "S.O. No. 2989".

[No. 19(63)/77-CL]

S. R. A. RIZVI, Director

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का० आ० 2890.—बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए० एस० मोहिन्द्रा, आई०ए० एण्ड ए०एस०, वरिष्ठ उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार-II, बिहार को एतद्द्वारा 22 मई, 1978 के अपराह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 18(70)/76-गं०वे०]

सुरेन्द्र बहादुर खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2890.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri A. S. Mohindra, I. A. & A. S., Senior Deputy Accountant General, Office of Accountant General II, Bihar as Financial Adviser, Betwa River Board, Jhansi for a period of 3 years from the afternoon of 22nd May, 1978.

[No. 18(70)/76-GB]

S. B. KHARE, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1978

आदेश

का०आ० 2891.—केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) तथा नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या 17/2/68-वी, दिनांक 25 जून, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश, अनुसूची में, "(2) अधीनस्थ कार्यालय (क) रेडियो स्टेशन—" शीर्ष के अन्तर्गत, मद (ग) तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद तथा तत्संबन्धित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
(घ) विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी :				
सभी पद	सहायक केन्द्र इंजीनियर	सहायक केन्द्र इंजीनियर	सभी	केन्द्र निदेशक (विज्ञापन)

[संख्या आई-14013/1/75-स्पेशल/विजीलेंस]

श्रीमती कान्ति देव, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 5th July, 1978

S.O. 2891.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that the following amendment shall be made in the Order of the Government of India in the Ministry of Information & Broadcasting No. 17/2/68-V, dated the 25th June, 1971, namely :—

In the Schedule to the said Order, in part II under the heading "(ii) Subordinate Offices : A. Radio Stations :—", after item (c) and the entries relating thereto, the following item and entries relating thereto be inserted, namely :—

1	2	3	4	5
"(d) Commercial Broadcasting Service, All India Radio :				
All posts	Assistant Station Engineer	Assistant Station Engineer	All	Station Director (Commercial)

[No. I-14013/1/75-Spl/Vig]

SMT. KANTI DEB, Under Secy

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

आदेश

का० आ० 2892.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, गोदावरी खानी, करीमनगर जिला (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सी० एल० नरसिम्हाराव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के प्रबन्धतंत्र की, श्री वी० वेंकटैया, मोटर ड्राइवर को, जिसका नाम कम्पनी के रजिस्टर से मंजूर की गई छुट्टी से अधिक ठहरने के कारण हटा दिया गया था, बदली फिल्लर की नौकरी देने की कार्रवाई न्यायोचित है ; यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ;

[फा०सं० एल-21012/7/78-डी० 4(बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1978

S.O. 2892.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Limited Godavari Khani, Karimnagar District (Andhra Pradesh) and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri C. L. Narasimha Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited in offering Badli Filler's job to Shri V. Venkataiah, Motor Driver, whose name was removed from Company's rolls for overstaying the period of sanctioned leave is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[F. No. L-21012(7)/78-L-IV(B)]

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1978

आदेश

का०आ० 2893.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, येलान्दु डिवीजन, खम्मम जिला (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सी० एल० नरसिम्हा राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम के सिंगरेनी कोलियरीज येलान्दु डिवीजन के प्रबन्धतंत्र की, जवाहर खानी नं० 1 खान के भूतपूर्व कोल फिल्लर श्री हुसैन मिया को, 15-12-75 से सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ; यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ;

[फा०सं० एल-21012/8/78-डी० 4 (बी०)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1978

S.O. 2893.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Yellandu Division, Khammam District (Andhra Pradesh) and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri C. L. Narasimha Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited, Yellandu Division of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium in dismissing Shri Hussain Mia, Ex-Coal filler in Jawahar Khani No. 1 Mine from service with effect from 15-12-75 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[F. No. L-21012(8)/78-D-IV(B)]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1978

आदेश

का० आ० 894.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, गोदावरी खानी नं० 5 इनक्लाइन, रामागुंडम डिवीजन-II, करीमनगर जिला आन्ध्र प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री सी०एल० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के प्रबन्धतंत्र की, गोदावरी खानी नं० 5 इनक्लाईन, रामागुंडम डिवीजन-II के भू पूर्व शॉट फायरर, श्री साकली रायालिंगु की सेवा को, 28/10/77 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ; यदि नहीं, तो संबन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[फा० सं० एल-21012 (6)/78-डी-4-(बी)]

भूपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1978

S.O. 2894.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employees in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Godavari Khani No. 5, Incline, Ramagundam Division-II, Karimnagar District, (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri C. L. Narasimha Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Shri Sakali Rayalingu, Ex-Shot Firer, Godavari Khani No. 5 Incline, Ramagundam Division-II with effect from 28-10-1977 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[F. No. L-21012(6)/78-D-IV(B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

का०आ० 2895.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में गुआली आयरन ओर माइन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम०वी० रंगाराजु होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स एम०एच० रहमान की गुआली आयरन माइन के चालान क्लर्क, श्री राघव महाकुद की सेवा से बरखास्तगी न्यायोचित है ; यदि नहीं, तो असन्तुष्ट कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ;

[सं० एल-26012/6/78-डी-III]

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1978

S.O. 2895.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Guai Iron Ore Mine and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government consider it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which M. V. Rangaraju shall be the Presiding Officer with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the dismissal of Shri Raghab Mahakud, Challan Clerk from service in the Guali Iron Mine of M/s. M. N. Rahman is justified? If not, to what relief is the aggrieved worker entitled.

[No. L-26012/6/78-DIII[B]

S.O. 2896.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Oil India Limited Duliajan and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No. 22 of 1974

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Oil India Limited, Duliajan,

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employees :

Sri J. K. Ghosh, Advocate, along with Sri A. K. Joardar, Advocate, and Sri A. Bez Baruah, Industrial Relations Superintendent.

On behalf of Workmen :

Sri Bashi Chakravorty, President, Oil India Contractors Workers Association & Sri Khitish Sarkar, General Secretary, Oil India Contractors Workers Association.

State : Assam Industry : Oil

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-30011 (3) [73. LR. IV dated 21st November, 1974, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Messrs. Oil India Limited, Duliajan and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads as follows :

> "Whether the workmen working as casual labour at Messrs Oil India Limited, Duliajan are under the employment of the principal employer of Messrs Oil India Limited ? If so, to what relief are such workmen entitled to in the matter of employment against the regular and permanent jobs under the principal employer ?"

2. This is Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. After notice of the reference was served on the parties, an application was made by the management in the High Court at Calcutta under Article 226 of the Constitution questioning the validity of the reference. In that application the Hon'ble High Court issued a Rule and granted ad-interim injunction restraining this Tribunal from proceedings further with the conduct of the reference. Thereafter by an Order dated July 19, 1978 made by consent of parties T. K. Basu, J, disposed of the Rule being Civil Rule No. 71 W.

of 1975 in that case in accordance with the terms of settlement filed in the Court by the parties. The said terms of settlement were as follows :—

"The petitioner, Oil India Ltd. and the Respondents Nos. 3 and 4 viz. Oil India Contractors Workers Association and the workers represented by Oil India Contractors Workers Association jointly state as follows:

That the parties have reached an amicable settlement out of Court as a result whereof they do not wish to proceed with the present adjudication referred to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta by the Central Government under the order of reference dated the 21st November, 1974 which is the subject matter of the present rule.

2. In view of the amicable settlement reached between the parties out of court, the parties jointly pray that the present Rule may kindly be disposed of in terms of this joint petition. The parties further pray that this joint petition may kindly be made a part of the order of this Hon'ble Court."

3. Pursuant to the disposal of the said rule in accordance with the terms of settlement, the parties filed a joint petition dated 19th July, 1978 before this Tribunal. By the said petition the parties stated that they had reached an amicable settlement out of court as result of which the present reference does not call for any adjudication and prayed for disposal of the reference on the basis of a 'no dispute' award. A copy of the said petition is annexed hereto as part of this Award.

4. In the result, I make a 'no dispute' award in respect of the industrial dispute involved in this reference.

S. K. MUKHERJEE Presiding Officer

Dated, Calcutta,
The 29th August, 1978
Seal

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

In the matter of an Industrial Dispute under Government Order of Reference dated 21st November, 1974

BETWEEN
Oil India Ltd., Duliajan
AND
Their workmen

Both parties jointly state as follows :

1. The casual labour involved in the present adjudication are represented by Oil India Contractors' Workers Association, Duliajan at whose instance the present reference has been made.

2. The said workmen represented by the said Association on one hand and Oil India Limited on the other have reached an amicable settlement out of Court as a result of which the present reference does not call for any adjudication.

3. The parties therefore, jointly pray that the learned Tribunal would be pleased to dispose of the present reference on the basis of a no-dispute award.

The parties jointly pray for a no-dispute award accordingly

FOR OIL INDIA LTD.
Sd/-
ANAND BAZBARUAH, 19-7-1978
Indusrial Relations Superintendent.

For the Casual Labour represented
by Oil India Contractors' Workers'
Association.
Sd/-
Bashi Chakravorty, 19-7-78
Present.
Sd/-
Kshitish Sarkar, 19-7-1978
General Secretary.

S. K. MUKHERJEE, Presiding Officer
[No. L-30011/3/73 CR IV]

Seal

New Delhi, the 16th September, 1978

S.O. 2897.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st September, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 47 of 1977

PARTIES :

Employer's in relation to management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri Ashoke Sarkar, with Shri S. N. Misra, Asstt. Law Officer (Mines).

For the Workmen.—None

STATE : Bihar. INDUSTRY : Copper

Dated, the 28th August, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-43012/1/75-D-IV(B) dated the 26th August, 1975 for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum, in striking off the rolls the name of Shri Naiki Hoe, Timber Mazdoor of their Surda Mine with effect from 25-12-1973 was justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. As will be clear from the schedule re-produced above the dispute relates to the illegal termination of service of Sri Naiki Hoe. This dismissal was in fact an individual dispute which could be transformed into an industrial dispute if any representative union of the industry raised the dispute on behalf of the workmen. The introduction of Section 2A of the Industrial Disputes Act permits even the workman himself to raise such an individual dispute as if it was an industrial dispute. In the present case this dispute was not raised by the workman himself under Section 2A of the Industrial Disputes Act. In purports to have been raised by Shri R. K. Nair who styled himself as General Secretary of Mosaboni Mines Labour Union. The management's objection was that Sri R. K. Nair was neither a workman of the industry nor he ever was General Secretary or any other office bearer of the said union at or about the relevant time when the dispute was raised or when the service of the workman was terminated. On this preliminary point parties were asked to lead evidence. Sri Nair did not appear inspite of proper service of notices sent to him twice. The management produced a list of the Office Bearers, Executive Committee Members and Co-opted Members of the Mosaboni Mines Labour Union for the year 1971-72 and another which is in vogue at present. On my insistence the management further produced Sri Boden Majhi, Treasurer of the Union mentioned in the list of the Office Bearers of 1971-72 Ext. M-1. It further produced Sri Jagannath Majhi, Vice President of the said Union at present vide list Ext. M-2. Both of them stated before me that the Office Bearers of 1971-72 continued till they were re-placed by fresh election vide Ext. M-2. They further stated that Sri R. K. Nair had never been the Office Bearer of that union. No other union with Sri Nair as its Office Bearer exists or is operating in Mosaboni Mines. From this uncontroverted evidence it is clear that the dispute was raised by a person who was not the Office Bearer of union of which he posed to be the General Secretary. Thus neither the workman nor any union operating in Mosaboni Mines raised the dispute. Hence the question of termination of services of Sri Naiki Hoe never assumed the shape of an industrial dispute. No valid reference could therefore be made. As such it is held that the reference is not maintainable. Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer
[No. L-43012/1/75-D-IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1678

का० आ० 2898—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० वी० गंगाराजु होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स उड़ीसा माइनिंग लि०, भुवनेश्वर की दायत्री आयरन और माइन्स के कर्मकारों की फील्ड भत्ते की मात्रा को संशोधित करने की मांग न्यायोचित है ; यदि हाँ, तो असन्तुष्ट कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ;

[सं० एल:-26012/3/77-डी० 3 (बी)]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2898.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Orissa Mining Corporation Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (i) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. V. Ganga Raju shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen of Daitari Iron Ore Mines of M/s. Orissa Mining Limited, Bhubaneshwar for revision of quantum of field allowance, is justified ? If so, to what relief are the aggrieved workmen entitled ?

[No. L-26012/3/77. DIII-B]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1978

का०आ० 2899—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 975 तारीख 17 मार्च, 1978 द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ के लिए 17 मार्च, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 सितम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11019/3/78-डी० 1(ए)(i)]

New Delhi, the 16th September, 1978.

S.O. 2899.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 975 dated the 17th March, 1978 the Zinc Mining Industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 17th March, 1978 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period for six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 17th September, 1978.

[No. S. 11017/3/78|DI(A) (i)]

का०आ० 2900—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 857 तारीख 14 मार्च, 1978 द्वारा सीसा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 मार्च, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 25 सितम्बर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11019/3/78-डी० 1(ए)(ii)]

S.O. 2900.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 857 dated the 14th March, 1978 the lead mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 25th March, 1978;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of powers confered by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 25th September, 1978.

[No. S. 11017/3/78|DI(A) (ii)]

का०आ० 2901—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 856 तारीख 14 मार्च, 1978 द्वारा तांबा खनन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अक्तूबर, 1978 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस० 11017/3/78-डी० 1(ए)(iii)]

एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

S.O. 2901.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 856 dated the 14th March, 1978, the Copper Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 1st April, 1978;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercis of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 1st October, 1978.

[No. S. 11017/3/78DI(A) (iii)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 2902.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of 12 Stevedores at Mormugoa Harbour (Goa) and their workmen which was received by the Central Government on the 12th September, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/16 of 1975

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of :

1. Messrs Agencia Commercial Maritima, Vasco-da-Gama (Goa).
2. Messrs Agencia Ultramarina Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
3. Messrs Chowgule Brothers, Mormugao Harbour (Goa).
4. Messrs Damodar Mangalji and Company (Private) Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
5. Messrs Eleabao Pereira and Sons, Vasco-da-Gama, (Goa).
6. Messrs Machado and Sons, Agents and Stevedores Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
7. Messrs Gosalia Shipping Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
8. Messrs Lima Leitao and Company, Mormugoa Harbour (Goa).
9. Messrs Mormugoa Navegadore Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
10. Messrs Rajaram V. Redij, Vasco-da-Gama (Goa).
11. Messrs V. M. Salgaocar and Brothers Private Limited, Vasco-da-Gama (Goa).
12. Messrs V. S. Dempo and Company Private Limited, Mormugoa Harbour (Goa).

AND

Their Workman

Shri Ligambar Narayan Hadfadkar

INDUSTRY : Ports and Docks

STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 31st July, 1978

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication by their order No. L-36012(1)/75-D.-IV/A dated 19-8-1975 :—

"(a) Whether the Stevedores of Mormugoa Harbour specified in Schedule I are justified in refusing employment to Shri Digambar Narayan Hadfadkar, Temporary Winchman (Registration No. 408-D) with effect from the 8th October, 1974 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

The employers have filed a common written statement stating that there is no employer-employee relationship between them and the workman and that by virtue of the provisions of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 and the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, it was the Dock Labour Board that is the appointing authority. They referred to several provisions of the Act in support of their case. On the merits they submit that their enquiries revealed that the workman herein was caught by the Central Intelligence Secruity Force on 21-7-74 at about 3.45 hours while carrying a bag containing Calcium Ammonium Nitrite. They further learn that the Sub-Inspector of Police of Marmagoa Harbour suggested to the Traffic Manager of the Port Trust on 12-8-74 that as several thefts were taking place in the ships the Port authorities should impose some restrictions on the issue of Port entry permits. He also requested the Port authorities to screen the persons already holding entry permits. A verification of the antecedents of some of the Port Trust employers revealed that the workman herein had some previous convictions for theft to his credit. Therefore the Port authorities cancelled the Port entry permit issued to the workman. This rusulted in the services of the workman being terminated. In fact he was unable to offer himself for service before the Dock Labour Board without proper entry permit.

At the request of the Employers, Mormugao Dock Labour Board was called upon to show cause why it should not be impleaded as a party to this reference. They appeared before this Court and filed a counter giving several reasons in support of their contention that they were not a necessary or proper party to this reference. After hearing the Employers and the Mormugao Dock Labour Board this Court directed by its order dated 16-3-1978 that the Dock Mormugao Dock Labour Board should be brought on record as a party to this Reference.

The workman was originally represented by the Goa Dock Labour Union. Till 18-11-1977 the Union did not file any statement of claim on behalf of the workman. On 18-11-1977 a Memo. was filed by the General Secretary of the Union informing the Court that the Union might be permitted to withdraw its appearance from this case. Along with this Memo is filed a copy of the letter dated 9-11-1977 issued by the Union to the workman herein informing him that since he was not given them proper instructions for the preparation of the statement of claim they were withdrawing their appearance. That Memo. was allowed and a notice was directed to be issued to the workman for the hearing date 31st January, 1978. The workman did not appear on that hearing date. Again another notice was issued to the workman to file his claim statement by 15-6-78. This notice was issued to one Atmaram Bhiku Penekar, in whose care the workman was said to be staying. This notice was returned with the endorsement 'refused'. Therefore another notice under certificate of posting was issued requiring the workman to file his statement of claim on 31-7-1978. To this notice there was no response from the workman.

In the circumstances this reference is closed for non-prosecution.

This reference is answered against the workman for non-prosecution.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-36012(1)/75-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 18th September, 1978

S.O. 2903.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kustore Sub-Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, at and Post Office Kustore, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th September, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947.

Reference No. 7 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kustore Sub-Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited At & Post Office Kustore, District Dhanbad.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers :Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen : Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, the 31st August, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. L-20012/103/76-DIIIA, dated 7-2-1977, for the adiudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Area No. VIII Kustore Sub-Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kustore, District Dhanbad in reverting the following 45 workmen (List enclosed with the award as Annexure I) of the said Area with effect from 25th/26th July, 1975, is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

2. It is not disputed that Sri J. S. Jootla, Area General Manager who had tendered his resignation in December, 1974 and was marking time for three months notice to expire, granted promotions or upgraded the posts on which the said workmen were working. The successor Area General Manager cancelled those orders and reverted them back to their original posts and grades subject to the protection of emoluments which they were drawing in the higher posts or grades at the time of reversion. The difference between the grade pay of the reverted post or scale and the emoluments which they were getting at the time of reversion were ordered to be gradually absorbed in future increments.

3. The case of the union is that Sri J. S. Jootla had the powers to pass such orders of promotions and upgradation. He did so after examining each case sponsored by the union. The well considered orders could not be so taken back after six months of their implementation to the disadvantage of the workmen. This was illegal and without jurisdiction.

4. The case of the management is that the orders were malafide and were passed in utter disregard of seniority and capability etc. and in flagrant violation of the total ban on promotions and upgradation imposed by the Central office. The posts were upgraded for no reason and thus the whole set up of the wage board was disturbed giving rise to a cause for disturbance in other areas. There was good deal of agitation and number of representations for reviewing the orders which were unfair, arbitrary and contrary to all rules of natural justice, were received by Sri K. P. Singh, the successor Areat General Manager. Proper procedure was not followed. These promotions and upgradations if allowed would cause unrest in the whole of the coal industry. Due notice of revocation of the orders passed by Sri Jootla in this respect was given. Now after consulting D. P. C., holding interviews and tests promotions shall be granted. The reversion orders were not illegal.

5. The orders dated 22-9-77 passed in Gokuldih Area No. IX vide Ext. W-7, dated 27-9-77 passed in Kendwadih Area No. VII vide Ext. W-8 and dated 30-9-77 passed in Kustore Area No. VIII vide Ext. W-9 as well as the testimony of Sri K. P. Singh, the then Area General Manager of Kustore Area No. IV, establish that Area General Managers had the powers to promote the workmen and upgrade the posts. But vide letter No. BCCL/IR-101|4(40)|73|60751 dated 26-12-73 issued by Chief Industiral Relations and Personnel, which is referred in Ext. M-5, the General Managers were advised 'not to upgrade any person' at that juncture when the entire wage structure was in the process of revision through the Joint Bipartite negotiating Committee. This letter virtually withdrew or suspended the General Managers' powers to upgrade posts or promote persons in their area. Sri Jootla's orders were thus passed in flagrant disregard of those orders of his superior authority. The successor General Manager had thus a right to review them. No order by way of a precedent has been filed beofre this Tribunal under which any Area General Manager of his own, ever since the issue of that letter dated 26-12-1973, upgraded any post or promoted any person till the National Coal Wage Agreement came into force in the year 1975. All the aforesaid orders of upgradation or promotion relate to a period subsequent to the year 1975.

6. Sri K. P. Singh, the then Area General Manager is categorical in his statement that after nationalisation there was no appreciable increase in work load of the clerks and other workmen. He stated that wherever and whenever the work load increased the man power was also increased with the result that now the company is facing the problem of large surplus of man power. Noither any reason has been given by Sri Jootla in his order nor any paper on which such reason might have been given is produced before this Tribunal nor the union has produced any evidence to show as to how and why upgradation of the post was necessary. There appears to be no obvious reason for doing so. The lone fact that a workman was working on a particular post for a long period was not sufficient to upgrade his post. For this reason also the orders with respect to upgradation could not be said to be justified orders and therefore they were rightly revised.

In the Chart Ext. W-4 majority of these workmen fall under the category of upgradation of posts because neither their designations nor place of work nor nature of work was changed.

7. However to my mind the few cases of promotion to a post of higher responsibility do deserve slightly different consideration. They were not reverted on account of the powers being kept in abeyance. Had they been regular the succeeding manager might have not disturbed them inspite of the fact that when these orders were passed the powers were kept in abeyance. Promotion orders if otherwise justified could not adversely affect the Bipartite Negotiations of Settling National Wage. The sole ground of reversion was that the claims of others were not properly considered and principles of natural justice were not followed.

8. The union has asserted that the Sub-Area Manager discussed individual cases with the sponsoring union, he then made recommendations which were considered by the Area General Manager who had consultations with the Area Personnel Manager and then the promotion orders were passed. Sri K. P. Singh by passed the personnel manager, relied upon his subordinate Senior Personnel Officer and passed reversion orders with immediate effect. No notice was given to the affected persons nor they were afforded any opportunity to make a representation. Mere seniority is never the sole ground for promotion. What other considerations weighed with the outgoing manager could well be spelled out by the personnel manager but he was not taken into confidence. Formation of D.P.C. was not a sine qua non for promotions. There was no such system in vogue at that time. In fact those five who had moved an application challenging the validity and propriety of those promotions, were not the affected persons because even inspite these reversions they have not been benefitted. The management has not produced any evidence to show that such and such senior workmen were superseded for no fault by such promotions. Thus there was no reason to jump to a conclusion that the promotion orders were malafide or irregular and violative of principles of natural justice. The orders were passed without giving prior notice and without affording any opportunity to the affected persons to explain, hence the orders were arbitrary, capricious and unjustified.

9. The case of upgraditions of posts was different because the workmen continued to discharge the same functions and responsibility and as said above the upgradation was totallv unjustified.

10. It is therefore ordered that out of the list of these 45 workmen the cases of those whose posts were simply upgraded deserve no consideration as their reversion to the original grade was not unjustified.

11. Those of the workmen listed in Annexure I to this award, who were promoted by Sri Jootla to a post of higher responsibility, shall be reinstated back to those posts and shall be paid the difference of wages from the date of reversion to the date of reinstatement as if they continued to be on the same promoted posts. The management, however, will have an option to re-examine each one of these individual cases of the employees so promoted after giving them an opportunity to represent their cases and thereafter, if for some valid reasons the management comes to the conclusion that any one or more of these promoted workmen was or were not rightly promoted and deserved to be reverted back to his or their substantive post or posts which he or they occupied before the promotion orders were passed by Sri Jootla, Then he or they may be so reverted back to his or their substantive post. Award is given accordingly.

Sd/-

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

ANNEXURE I

(Names of the workmen mentioned in the schedule of reference)

Sl. No.	Name of the workmen.	Designation.
1.	Sri Ambika Pd. Pandey.	Asstt. Store Keeper.
2.	Sri K. C. Roy.	Store Keeper.
3.	Sri R. N. Ghosh.	-Do-
4.	Sri D. K. Banerjee.	Asstt. Store Keeper.
5.	S. N. Chakravorty.	Store Keeper.
6.	Sri D. N. Dutta.	Accts. Clerk.
7.	Sri Satyenbei Mishra.	Store Keeper.
8.	Sri S. N. Dutta.	Clerk.
9.	Sri K. N. Gupta.	Accts. Clerk.
10.	Sri T. N. Nagi.	Clerk.
11.	Mrs. K. Sundaram.	-Do-
12.	Sri D. K. Sarkar.	-Do-
13.	Sri Sukumar De.	-Do-
14.	Sri P. D. Goswami.	-Do-
15.	Sri B. P. Bhattacharjee.	Cashier.
16.	Sri G. M. Banerjee.	P.O.'s Clerk.
17.	Sri Gurudas Dutta.	Asstt. Despatch Clerk.
18.	Sri P. K. Singha.	Clerk.
19.	Sri N. K. Paul.	-Do-
20.	Sri R. N. Banerjee.	-Do-
21.	Sri A. K. Ghosh Dastidar.	Clerk.
22.	Sri Raghubir Misra	-Do-
23.	Sri K. P. Dutta	-Do-
24.	Sri G. N. Sengupta.	-Do-
25.	Sri C. S. Bhattacherjee	-Do-
26.	Sri R. A. Rai.	-Do-
27.	Sri N. N. Singh.	Bill Clerk.
28.	Sri Yogender Singh.	-Do-
29.	Sri Purusottam Prasad.	Office Clerk.
30.	Sri N. R. Singh.	Relieving Clerk.
31.	Sri D. N. Singh.	General Clerk.
32.	Sri H. N. Singh.	Bill Clerk.
33.	Sri S. N. Banerjee.	Genl. Clerk.
34.	Shri B. K. Ghosh.	Bonus & P. F. Clerk.
35.	Sri N. N. Dey.	Bill Clerk.
36.	Shri N. N Singh.	-Do-
37.	Sri S. N. Singh.	H/C Superviser.
38.	Sri J. P. Singh.	Clerk.
39.	Sri A. K. Mallick.	Managing Incharge.
40.	Sri Mathura Paswan.	Clerk.
41.	Sri Beccha Singh.	Bonus Clerk.
42.	Sri S. N. Singh.	Bill Clerk.
43.	Sri Biswanath Singh.	Leave Clerk.
44.	Sri Nagendra Pd. Singh	Bonus Clerk.
45.	Sri Damodar Singh.	Gomasta.

S. N. JOHRI, Presding Officer

[No. L-20012/103/76-D. III(A)]

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2904.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shampur II Colliery of M/s. Coal Mines Authority Ltd., P.O. Nirsachatti (Distt. Dhanbad), and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th September, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947

Reference No. 62 of 1977

PARTIES : Employers in relation to the management of Shampur II Colliery of M/s. Coal Mines Authority Ltd. P.O. Nirsachatti (Distt. Dhanbad).

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen : Shri J. D. Lall, Advocate

STATE : Bihar. Industry : Coal.

Dated, 30th August, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-20012/136/75-D. III (A) dated 8-6-1976 for the adjudication of the following industrial dispute :

"Whether the action of the management of Shampur II Colliery of M/s. Coal Mines Authority Ltd., P.O. Nirsachatti, Distt. Dhanbad Area No. VI, in transferring Shri Gurbachan Singh, Pump Khalasi to Area No. V is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. It is not disputed that Sri Gurbachan Singh was an old and a permanent employee of the erstwhile private owner in Shampur II Colliery since before the take over of the mines by the Custodian. He was working as Pump Khalasi. The mine was nationalised with effect from 1-5-1973 and it came under the ownership of Government company known as Coal Mines Authority. Subsequently Messrs Eastern Coalfields Limited has now stepped into the shoes of Coal Mines Authority Ltd. There were no separate Standing Order, hence Model Standing Orders were applicable to the colliery when it was under the private ownership. When Gurbachan Singh returned back from leave, the authority in Shampur II Colliery did not allow him to join and said that he had been transferred to Area No. V from Shampur II Colliery which is situated in Area No. VI. The workman did not comply with the transfer Order and submitted sick certificate.

3. The case of the Union is that Sri Gurbachan Singh was an officer of Bihar Colliery Kamgar Union. The management of Shampur II Colliery wanted to crush the Union, hence it devised ways and means and it was in that process that Gurbachan Singh was transferred. The transfer effected a change in service conditions. His old service conditions did not empower the management to transfer him to present Area No. V. The transfer was a clear case of victimisation for trade union activities. The area to which he is transferred will have different Standing Orders and therefore again the transfer will result in the change in service conditions. The workman as well as the union made representations but the management did not need to them. The prayer is for the reinstatement in the same post at the same place.

4. The case of the management is that the purpose of nationalisation itself was to set up economical units with proper man power. It was decided at a high level that the transfer could be effected from one area to the other and it was in that process that due to the exigency of the situation Sri Gurbachan Singh was transferred to Area No. V. Standing Order applicable to Sri Gurbachan Singh does carry a clause for transfers from one Colliery to the other. The management was thus within it's right to order such a transfer. Neither the workman nor the union raised any dispute directly with the management on this point. The dispute was for the first time raised before the A.L.C. It is therefore alleged that no industrial dispute came into existence and the reference was not valid. Some of the workmen who had been transferred filed the regular Civil Cuit No. 4/8 of 1975 in Civil Court at Dhanbad. Learned Civil Judge granted injunction against the transfer. The management preferred an Appeal (Misc. Appeal No. 25 of 1975) against the injunction order to the District Judge who transferred the same to the Additional District Judge. It was agreed between the management and the sponsoring union on 7-5-1975 that the parties would abide by the decision given by the Additional District Judge in appeal. Ultimately that appeal against the injunction order has been allowed by the Additional District Judge and the injunction order stands vacated. It is therefore alleged that the union is bound by the agreement and unless that agreement is set aside the union has no right to press the claim against the transfer of Gurbachan Singh to Area No. V.

5. After the close of the case an application was moved before me at Calcutta by Sri K. S. Chatterjee. M. L. A. and Secretary of Bihar Colliery Kamgar Union. He wanted that the case may be re-opened and he may be given the chance to appear and depose in support of the union's case specially for proving that Sri Gurbachan Singh was a protected workman. I have considered this application and I am not inclined to re-open the case specially because the plea that Sri Gurbachan Singh was a protected workman was never before taken by the union. It might have been taken at the conciliation stage but in the written statement filed before his Tribunal that plea is absolutely wanting. On the other hand, there is a statement of Sri Gurbachan Singh himself that his name was not included in the list of the Office Bearers which was submitted to the management. The application for re-opening case is therefore rejected.

6. The first question is whether an industrial dispute came into existence before the refernce was made because the existence of an industrial dispute is sine-quanon for the making of a valid reference by the Government. It has been specifically alleged in the pleading of the union, and Sri Gurbachan Singh has also said in his deposition, that he submitted an application Ext. W-1 in writing to the management. Acknowledgement of the management's office is present on the copy of the original application Ext. W-1. The acknowledgement goes to show that this application was submitted on 16-4-1975 to the Manager. This amounted to raising the dispute directly with the management. Sri Gurbachan Singh W. W. 1 further stated that he made a second representation copy of which is Ext. W-2. There is no rebuttal to this evidence and it is held as proved that a dispute had been directly raised with the management.

7. Moreover it is admitted that the union referred the dispute to the A. L. C. who gave a notice of the same to the management. The management did not concede the demand. It is now the law settled by the Supreme Court that even if the dispute comes into existence through the intervention of A. L. C., before the reference, the same shall give rise to a valid reference. I am therefore of the view that the plea of invalidity of the reference has no force.

8. Another plea has been raised that the order passed by the Additional District Judge, Dhanbad on 25-11-1975 in Misc. Appeal No. 25 of 1975 read with the minutes of discussion held with the management of Coal Mines Authority Limited and Bihar Colliery Kamgar Union on 7-5-1975 constituted an agreement between the union and the management that they shall abide by the decision of the Additional District Judge and since the District Judge held that the management had an absolute right to transfer, the union is bound by it and cannot now raise an objection to the transfer of Sri Gurbachan Singh unless the agreement is set aside. The plea has no force. The Mis. Appeal was filed against the order of injunction passed by the Additional Sub-Judge in Title Suit No. 4/8 of 1975 on 24-3-1975. That Suit was filed by Ramji Tewari and others. The appellate order mentioned that the transfer orders passed on 28-1-1975 were invalid. There is no evidence to show that the transfer order against Sri Gurbachan Singh was passed on 28-1-1975. In the application Ext. W-1 Gurbachan Singh said that his case was similar to those who were involved in the said Title Suit. This clearly meant that he was not one of the plaintiffs in that Suit. Sri Gurbachan Singh had been on leave upto 16-2-1975 and when he was not allowed to join on that date be made representation vide Ext. W-1 and W-2 in April, 1975. Therefore the decision in that Civil Suit or appeal can have no binding effect on Gurbachan Singh or the union which was again not a party to that case.

9. Secondly observations made while holding that there was no prima facie case cannot be held sufficient to decide the rights of the parties finally. There is no final agreement or settlement recorded. Only the minutes of the meeting have been filed and they make mention of transfer of 8 workmen and transfer of 9 workmen. Again there is no evidence that the case of Gurbachan Singh was included in those 8 and 9 workmen contemplated in the minutes of discussion.

10 Thirdly the Civil Courts have no jurisdiction to entertain a suit relating to an industrial dispute. The decision given without jurisdiction has hardly any binding effect and the opinion expressed about the prima facie case without jurisdiction cannot be validated by an agreement which has not been formally recorded in the form prescribed by the Rules. Bar of S. 19 does not apply to such an agreement and the same cannot therefore oust the jurisdiction of this Tribunal to decide the industrial dispute on merits.

11. This brings us to the main question relating to the right of transfer. It is not disputed that there were no Standing Orders for Shampur II Colliery when it was under private ownership. The Model Standing Orders did apply. Clause 16 of the Model Standing Orders relating to transfer may be re-produced as follows :

"Workmen may be transferred due to exigencies of work from one Department to another or from one to

another or from one coal mine to another under the same ownership provided that the pay, grade station, continuity and other conditions of service of the workmen are not adversely affected by such transfer and provided also that if a workman is transferred from one job to another, that job should be of similar nature and such as he is capable of doing and provided further that (i) reasonable notice is given of such transfers and (ii) reasonable joining time is allowed in case of transfers from one station to another. The workman conierned shall be paid the actual transport charges plus 50 per cent thereof to meet incidental charges."

Even according to this clause it is necessary for a valid transfer that (i) it should arise out of the exigencies of the work, (ii) should specifically guarantee that pay, grade, continuity and other conditions of service shall remain unchanged, (iii) should be proceeded by a reasonable notice, and (iv) should allow reasonable joining time. In the present case a mountain has been sought to be raised out of the mole hill by speaking of the exigencies in the colliery to which Gurbachan Singh was transferred but it is obvious that a Fan Khalasi requires no technical qualification. Any workman can do the job and learn doing it in minutes. Of course he is a competent person. That is for the purposes of enforcement of Mines Safety Regulation only. Any workman there in area No. V could be so trained. The exigencies posed by the management are thus only the pretended exigencies.

12. Secondly no notice was given at all. Thirdly there is nothing in the orders to show that any joining time was allowed. The transfer was thus in breach of the conditions laid down by these Standing Orders that were applicable to the workman Sri Gurbachan Singh by virtue of provisions of Nationalisation Act.

13. Going a step further I am of the view that clause 16 of the Standing Orders did not give any right to the management to transfer Sri Gurbachan Singh from Shampur II Colliery to Area No. V. Admittedly the erstwhile private owner of Shampur II Colliery under whom Sri Gurbachan Singh started the service, had no colliery of its own in the present area No. V. Sri Gurbachan Singh admitted in his depositon that besides Shampur II the erstwhile owner had two more collieries one at Bhurungia and other at Diamond Tisra. Thus clause 16 of the Model Standing Orders can only be read to mean that erstwhile owner had a right to transfer those workmen to any of those three collieries which he owned at the time when Sri Gurbachan Singh joined the service. But clause 16 does not say that erstwhile owner had a right to transfer the employee to any other colliery which he might subsequently acquire. This restrictive condition of service in the matter of transfer continued to govern applicant after Nationalisation. Therefore it cannot be said that after nationalisation when Shampur II vested in Coal Mines Authority that compnay could transfer Sri Gurbachan Singh to any other colliery which it acquired in the course of nationalisation. In Kundan Sugar Mills vs. Ziauddin—6 SCLJ. the Supreme Court after distinguishing several cases very clearly observed on page 3839 that—

> "When the respondents 1 to 4 were employed by the appellant, the latter was running only one factory at Amroha. There is nothing on record to indicate that, at that time, it was intended to purchase factories at other places or to extend its activities in the same line at different places. It is also not suggested that even if the appellant had such an intention, the respondents 1 to 4 had knowledge of the same. Under such circumstances, without more it would not be right to imply any such term between the contracting parties when the idea of starting new factories at different places was not in contemplation. Ordinarily, the employees would have agreed only to serve in the factory then in existence and the employer would have employed them only in respect of that factory."

Again on page 3841 the Supreme Court held that—

> "it was not a condition of service of employment of the respondents either express or implied that the employer has the right to transfer them to a new concern started by him subsequent to the date of their employment."

In the present case also when Sri Gurbachan Singh started the service with the erstwhile employer he could not envisage his transfer to any colliery other than the three which were then owned by the then employer. Nobody contemplated that a time would in the year 1973 that the collieries would be nationalised and several of them would be put under the common ownership of a Government company. It was never contemplated that the present Area No. V would ever come under the ownership of the then employer. Conditions of service have been safe-guarded by the provisions of Nationalisation Act. Drawing analogy from the aforesaid case it is obvious that even inspite of clause 16 of the Model Standing Orders the management had no right to transfer Sri Gurbachan Singh to Area No. V. The transfer was thus not justified.

14. Sri Gurbachan Singh shall therefore be reinstated back in service as Fan Khalasi in Shampur II Colliery with full back wages for the period during which he has been kept out of the job. The management shall further pay Rs. 50 as costs to the union. Award is given accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L-20012/136/75. D. III (A)]

S. H. S. ILER, Desk Officer

New Delhi, the 19th September, 1978

S.O. 2905.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Grindlays Bank Ltd., Bombay and their workman over the termination of services of Shri H. J. Engineer, permanent clerk which was received by the Central Government on the 4-9-1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-4 of 1977

Employers in relation to Grindlays Bank Ltd., Bombay.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the workmen.—Shri B. W. Vaidya, Advocate.

For the employers.—(1) V. V. Pai, Advocate. (2) Shri S. B. Naik, Operations Manager.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra

Bombay, the 26th August, 1978

AWARD

1. The Central Government by order dated 24-3-1977, in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

SCHEDULE

> "Whether the action of the management of Grindlays Bank Ltd., Bombay in terminating the services of Shri H. J. Engineer, permanent Clerk in Mahatma Gandhi Road Branch of the Bank with effect from 20-3-1975 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The workman, Shri H. J. Engineer, was a cashier in the Main Office of the Grindlays Bank Ltd., Bombay. By the High Courts Order dated 5-3-1975 (Ext. W-1) the workman was adjudicated insolvent on a Petition filed by a creditor. The Bank came to know about this from a Public Notice published in a newspaper and it terminated the services of the workman in terms of Section 10(1)(b) of the Banking Companies Act with immediate effect on payment of three months' salary and allowances in lieu of notice. On 14-5-1975 the Workman's Advocate sent a letter (Ext. E-2) to the Bank informing them that his client, Shri H. J. Engineer, had taken out a Notice of Motion in the High Court of Bombay praying that the Order of Adjudication declaring him insolvent passed against him be reviewed, rescinded or varied. The request made therein was not to take further action against his client. The Notice of Motion (Ext. W-2) was filed on

27-3-1975. The Order of the High Court dated 17-6-1975 (Ext. W-3) on the Notice of Motion is as follows :—

"Notice of Motion absolute. Order of Adjudication be set aside. Petition to be on Board on 15th day of July, 1975."

The final Order passed by the High Court dated 24-7-75 (Ext. E-4) is as follows :—

"Petition dismissed for want of prosecution. In view of the affidavit dated 14th April, 1975 of the Debtor order of Advertisement dispensed with."

3. The Bank has filed a statement of claim saying that the workman was governed by the Bipartite Settlement dated 8-11-1973 and paragraph 522(1) of the Sastri Award which provides for termination of services by three months' notice and in cases not involving disciplinary action for misconduct the employment of a permanent employee may be terminated by three months' notice or on payment of three months' notice pay or allowances in lieu of notice. As a result of the Public Notice published in newspaper that the workman had been adjudicated an insolvent, the Bank by its letter dated 20-3-1975 addressed to the workman terminated his services with immediate effect on payment of three months' salary and allowances in lieu of notice. The Bank has already paid three months' salary in lieu of notice and the net salary for the period from 1-3-1975 to 19-3-1975 and his gratuity amount. The Bank has also delivered to the workman a cheque being the amount of Provident Fund together with the Bank's contribution thereto. The contention of the Bank is that the workman having been at one time adjudicated insolvent, it was not open for the Bank under the law to continue him in service. This was a case of lawful and bona fide act of termination simpliciter in order to conform with the stipulation under provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

4. The statement of claim of the workman is that after the High Courts order dated 24-7-1975 dismissing the Order of Adjudication the workman informed the Bank about the above order and requested the Bank to reinstate him, but the Bank declined to do so and there was conciliation proceeding which ended in a failure report. According to the workman, the Order of termination is bad and illegal on the ground that no retrenchment compensation as per the provisions of Section 25(f) of the Industrial Disputes Act has been paid. It is also his contention that the High Court having dismissed the creditors' petition for adjudicating the workman as insolvent, it will be deemed that there had been no adjudication declaring him insolvent and, as such, the Bank should have reinstated him.

5. While setting out the facts of the case I have already set out the Insolvency Order dated 5-3-1975. This was set aside by the High Court on 17-6-1975. The Original Petition of the creditor came to be fixed for hearing and ultimately on 24-7-1975 the Original Petition was dismissed (vide Ext. E-4). If upon the Notice of Motion order of Adjudication was set aside, it will be deemed in law that there had been no order of adjudication and after the Original Petition was dismissed the only legal consequence would be that the workman was never declared an insolvent.

6. The learned Counsel for the Bank has referred to Section 10(b) and 46(4) of the Banking Regulation Act, and has argued thereupon that even if at any time the workman had been declared an insolvent and if he was retained in service the Bank would be liable for penal action. But, as I have already stated above, the order of insolvency having been rescinded the position in law would be that at no point of time the workman will be deemed to have been an insolvent.

7. It was argued for the Bank that provisions of Section 10 of the Banking Act cannot be controlled or overridden by the Insolvency Act or any other Act. In support of this contention reliance was placed upon the observation made towards the close of para 16 in the Central Bank of India and other Vs. their workman (1960 S.C.—12). The observation runs to this effect :—

"The express provisions of Sec. 10 must then override any other law for the time being in force, so far as the banking companies are concerned."

It seems to me the argument is misconceived. The above observation came to be made as a reply to the argument that the provisions of the Banking Act are not to be interpreted in derogation of the provisions of the Industrial Disputes Act but in addition thereto. This argument was negatived by pointing to the provisions of Sec. 2 of the Banking Act, and ending by making the above observation.

8. In the present case the essential qualification embodied in Sec. 2 of the Banking Act is not being ignored. Correct interpretation of Sec. 10 of the Act, which says that no Banking Company shall employ or continue the employment of any person who is or at any time has been adjudicated insolvent, is being made. Under Sec. 8(1) of the Insolvency Act, the Court may review, rescind or vary any order made by it under its insolvency jurisdiction. In the present case the High Court exercised powers under this section since the workman's petition dated 17-6-1975 (Ext. W-2) purported to be under this section. The effect of the order (Ext. W-3) passed by the High Court will be that the order of adjudicating the workman as an insolvent will be deemed to have not been made at all and restoring the workman to the original position. In other words, he would be deemed to have not been adjudged insolvent at all. That this will be the position in law follows from Gamoji Venkata Ramakrishnarao Vs. *Gullapali Sambamurti (1961 AIR—Madras, page 581).* It was held that "the effect of the annulment of adjudication was to bring about the state of affairs as if there had never been an adjudication and that the property was to be deemed to have been the property of the applicant on the relevant dates." This is the law and there is nothing special of insolvency law in this and I do not think this concept of law is in derogation of Sec. 10 of the Banking Act. As such, I find no merit in the submissions made for the Bank.

9. It was also argued on behalf of the workman that the termination of services amounted to retrenchment in terms of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act and necessitated payment of retrenchment compensation under Section 25F of the Act. In support of the above submission reliance has been placed upon the case of State Bank of India Vs. No. Sundaramoney (1976 I LLJ, page 478). This position clearly support the contention raised on behalf of the workman. It also emphasises and is also clear from the wordings of Section 25(f) that the retrenchment compensation has to be paid at the time of retrenchment. It is common ground that no retrenchment compensation was paid at that time nor it has been done up till now. That being so, in view of the aforesaid decision the termination order is clearly not in accordance with law and it must be set aside.

10. The workman had led evidence that since his termination of services he has been unemployed and he had applied for a job to M/s. Godrej & Boyce and to a Bank in 1975 & 1977 respectively, but he has not been offered any employment. His father is an earning member and he depends upon him. He is 39 years old and has a wife.

11. Regard being had to the view that I have taken of the matter and the fact that the workman has remained unemployed all along my award is that termination of services of Shri H. J. Engineer, permanent clerk in the Mahatma Gandhi Road Branch of the Bank with effect from 20-3-1975 is not justified and that he is entitled to be reinstated retrospectively with back wages.

12. Reference is answered accordingly.

J. NARAIN, Presiding Officer.

[No. L-12012/121/76-D.II.A.]

R. P. NARULA, Under Secy.

का०आ० 2906.—टर्मिनल बैलिस्टीक्स रिसर्च लैबोरेट्री, चण्डीगढ़ (जिसे इसमें उसके पश्चात् लैबोरेट्री कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा (1क) के अधीन कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 से छूट के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त लैबोरेट्री के कर्मचारियों द्वारा अंगीकृत की गई तथा उन पर लागू केन्द्रीय सरकार कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1964 के अधीन कुटुम्ब पेंशन के रूप में ऐसे कर्मचारियों को प्राप्य फायदे उन फायदों से कम नहीं है जो उक्त अधिनियम और कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन उसी प्रकार के किसी अन्य थापन के कर्मचारियों के लिए उपबन्धित किए गए हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त लैबोरेट्री को कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है,

शर्तें

(1) लैबोरेट्री छूट के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार की इजाजत के बिना कुटुम्ब पेंशन के रूप में प्राप्य फायदों की मात्रा को घटा नहीं सकेगा।

(2) नियोजक ऐसे लेखा रखेंगे, ऐसे विवरण प्रस्तुत करेंगे और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं देंगे जिसका निर्देश केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे।

(3) उक्त लैबोरेट्री की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के संचालन के सारे व्यय जिसमें लेखा रखना, लेखा और विवरण प्रस्तुत करना लेखाओं का अन्तरण भी आता है, नियोजक को वहन करना होगा।

(4) नियोजक जिसमें उक्त लैबोरेट्री की कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों की एक प्रति जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हों सारे संशोधन सहित, यदि कोई हो, लैबोरेट्री के सूचना पट्ट पर, उसकी मुख्य विशेषताओं के कर्मचारियों के बहुसंख्यक की समझ में आने वाली भाषा में अनुवाद के साथ, प्रदर्शित करेगा।

(5) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना लैबोरेट्री कुटुम्ब पेंशन स्कीम के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। जहाँ संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पहले कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

[सं० एस-35014/2/78-एफ०पी०जी०]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 1978

S.O. 2906.—Whereas the Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh (hereinafter referred to as Laboratory) has applied for exemption, from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under sub-section (1A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas, in the opinion of the Central Government the benefits in the nature of family pension under the Central Government Family Pension Scheme, 1964 adopted by an applicable to the employees of the said Laboratory are not less favourable to such employees than the benefits provided under the said Act, and the Employees' Family Pension Scheme, 1971 to employees in any other establishment of a similar nature ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified hereunder, the Central Government hereby exempts the said Laboratory from the operation of all the provisions of the Employees' Family Pension Scheme.

CONDITIONS

(i) The Laboratory shall not, at any time after exemption, without the leave of the Central Government, reduce the quantum of benefits in the nature of Family Pension.

(ii) The employer shall maintain such accounts, submit such returns and provide for such facility for inspection as the Central Government may from time to time direct.

(iii) All expenses involved in the administration of the family pension scheme of the said Laboratory including maintenance of accounts, submission of accounts and return, transfer of accounts, shall be borne by the employer.

(iv) The employer shall display on the notice board of the Laboratory a copy of the rules incorporating therein all amendments, if any of the family pension scheme of the said Laboratory as approved by the Central Government, alongwith a translation of the salient features thereof in a language understood by the majority of the employee.

(v) No amendment of the rules, of the family pension scheme of the Laboratory shall be made without the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner. Where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Central Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[File No. S. 35014/2/78-FPG]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1978

का०आ० 2907.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, के निम्नलिखित कार्यालयों के नामों को, उक्त उपनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है—

1. मुख्यालय, नई दिल्ली
2. प्रादेशिक कार्यालय, मध्य प्रदेश, इंदौर।
3. प्रादेशिक कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़।
4. प्रादेशिक कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रादेशिक कार्यालय, बिहार, पटना।
6. उप-प्रादेशिक कार्यालय, मेरठ।
7. उप-प्रादेशिक कार्यालय फरीदाबाद।
8. उप-प्रादेशिक कार्यालय, पुणे।

[सं० ए-12034(107)/78 पी एफ आई]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 21st September, 1978

S.O. 2907.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the names of the following offices of the Employees Provident Fund Organisation, an autonomous body under the Ministry of Labour, for the purposes of that sub-rule :—

1. Headquarters Office, New Delhi.
2. Regional Office, Madhya Pradesh, Indore.
3. Regional Office, Punjab, Chandigarh.
4. Regional Office, Rajasthan, Jaipur.
5. Regional Office. Bihar, Patna.
6. Sub-Regional Office, Meerut.
7. Sub-Regional Office, Faridabad.
8. Sub-Regional Office, Pune.

[No. A. 12034(107)/78-PFI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

(सीमा-शुल्क)

का०आ० 2908.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 6 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली में कार्य करने वाले संयुक्त निदेशक विशेष कार्य अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी (पुलिस) और अन्वेषण अधिकारी (आयकर) को उक्त अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (1) के अधीन सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर के कृत्य सौंपती है।

[सं० 187/फा०सं० 437/5/78-सीमा शुल्क]

एस० बासु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th September, 1978

CUSTOMS

S.O. 2908.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby entrusts to the Joint Director, Officer on Special Duty, Investigating Officer (Police) and Investigating Officer (Income-Tax) working in the Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi, the functions of an Assistant Collector of Customs under sub-section (1) of section 105 of the said Act.

[No. 187/F. No. 437/5/78-Cus. IV]

S. BASU Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

का०आ० 2909.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये तामचीनी के बर्तनों को निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने के लिये कतिपय प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 2023 तारीख 24 सितम्बर, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 1 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित किये गये थे ;

और उनसे सभाव्यत: प्रभावित होने वाले सभी लोगों से 18 नवम्बर, 1977 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 4 अक्तूबर, 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अत: अब निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ 1277, तारीख 25 अप्रैल, 1966 को अधिक्रांत करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, और यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, केन्द्रीय सरकार—

(1) अधिसूचित करती है कि तामचीनी के बर्तन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) तामचीनी बर्तन निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे तामचीनी के बर्तनों पर निर्यात से पूर्व लागू होगा ;

(3) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए, तामचीनी के बर्तनों के लिये निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों के रूप में निर्यात कर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों को तामचीनी के बर्तनों के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, ऐसे तामचीनी के बर्तनों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित, अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे तामचीनी के बर्तन निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य है ।

2. इस आदेश में 'तामचीनी से बर्तनों' से घरेलू तथा अस्पतालों के प्रयोग के लिये कर्चसम तामचीनी (पोसिलिन इनेमल) से बनी वस्तुयें अभिप्रेत हैं ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू-मार्ग, जल-मार्ग या वायु मार्ग से तामचीनी के बर्तनों के उन नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिसका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपये से अधिक नहीं है ।

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

उपाबन्ध

[पैरा 1 (3) देखिए]

तामचीनी के बर्तनों के लिये विनिर्देश

1. सामग्री

1.1 इस्पात की चादर का माप क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा

2. आकार तथा विमायें :

2.1 तामचीनी के बर्तनों का डिजाइन विमाओं संबंधी विवरण तथा क्षमता क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करारनामें के अनुसार होंगे । उनकी सह्यताएं निम्नलिखित के अनुसार होंगी :—

विभाएं	±	2.5 प्रतिशत
क्षमता	±	2.5 प्रतिशत

3. कारीगरी तथा परिसज्जा :

3.1 बर्तनों की सतह में कोई भी दोष जैसे, पिनछिद्र, तड़कन या करार नहीं होंगे। बर्तन चिकनाना से मुक्त होंगे।

3.2 तामचीनी के बर्तनों की परिसज्जा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करारनामें के अनुसार चमकदार या द्युतिहीन होगी तथा तामचीनी का रंग, बनावट तथा मोटाई एक समान होंगे ।

4. परखें :

4.1 तामचीनी के बर्तनों के नमूने सुसंगत राष्ट्रीय या अन्तर-राष्ट्रीय मानक या नीचे दिये गये पैरा 4.2, 4.3, 4.4 तथा 4.5 के अनुसार प्रतिघात प्रतिरोध परख, शमन परख (केवल पकाने वाले बर्तनों के लिये), लीक परख (केवल जोड़ों वाले तामचीनी के बर्तनों के लिये) तथा अम्ल प्रतिरोध परख की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

4.2 प्रतिघात प्रतिरोध :—जब तामचीनी के बर्तनों की सतह पर 100 ग्राम भार वाले इस्पात की गेंद को 57 सें० मी० की ऊंचाई से निर्बाध रूप से गिराया जायेगा तो उसमें कोई गढ़ा नहीं बनेगा या उसकी सतह का बड़ा भाग विस्तृत नहीं हो जायेगा।

4.3 शामक परख (केवल पकाने के बर्तनों के लिये) नमूने को कम से कम 10 मिनट के 185. सी से 195. सी तक परख किया जायेगा तथा 15. सी से 20. सी तक पानी में तुरन्त बुझाया जायेगा गर्म तथा बुझाने की क्रिया को छः बार दुहराया जायेगा। इनेमल की गई सतह का छः बार परख चक्रों में से निकालने के पश्चात् किसी भी प्रकार की पपड़ी के उतरने अथवा क्रेजिंग के किसी भी निशानों के लिये परीक्षण किया जायेगा।

4.4 लीक परख :—तामचीनी के बर्तन को कम से कम 10 मिनट के लिये इमोसाईन के रंगीन पानी में रखा जायेगा। परख के दौरान, रंगीन पानी बर्तन में छाना नहीं जायेगा।

यह परख केवल जोड़ लगे तामचीनी के बर्तनों पर ही लागू होगी।

4.5 अम्ल प्रतिरोध परख :—तामचीनी के बर्तन की सतह को एसिटोन से साफ करके और सुखा कर गन्दगी एवं चिकनाई दूर की जायेगी। तामचीनी की साफ की गई सतह पर 3 सें० मी० व्यास का पतला फिल्टर कागज रखा जायेगा। जिसके ऊपर 2.5 सें०मी० व्यास का मोटा फिल्टर कागज रखा जायेगा। साइट्रिक एसिड घोल (100 ग्राम/लिटर) फिल्टर कागजों पर तब तक डाला जायेगा जब तक कि वे पूरी तरह तर न हो जायें। तब फिटर कागजों को वाष्पीकरण से बचाने के लिये वृश्य काँच से ढक दिया जायेगा। 20± 1 मिनट के पश्चात् फिल्टर कागज हटा दिये जायेंगे। तथा सतह को नल के बहते हुए पानी में धोया जायेगा तथा साफ कपड़े से सुखाया जायेगा। तामचीनी में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् चमक में कोई कमी नहीं आयेगी। साधित तथा असाधित दोनों ही सतहों पर एच बी पेंसिल से आर-पार चिन्ह खींचा जाये, तो साफ सूखे कपड़े से रगड़ जाने के पश्चात् एक सतह का चिन्ह दूसरी सतह के चिन्ह से अधिक देर तक नहीं रहेगा।

5. पैकिंग :

5.1 तामचीनी के बर्तन क्रेता के अनुबन्ध के अनुसार इस ढंग से पैक किये जायेंगे जिससे कोई नुकसान हुए बिना बर्तनों का गन्तव्य स्थान तक पहुँचना सुनिश्चित हो जाये।

5.2 37 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज, 150 सें० मी० की ऊंचाई से गिरने पर ठीक बने रहेंगे और पैकेज या उसमें रखे माल को कोई नुकसान नहीं होगा। पैकेजों की मौसम के के प्रतिकूल प्रभावों एवं आर्द्रता संदूषण से पर्याप्त सुरक्षा की जायेगी।

6. अनुरूपता के लिये नमूना लेना तथा मापदण्ड

प्रत्येक परेषण का नमूना तथा निरीक्षण नीचे दी गई सारणियों (i) तथा (ii) में वर्णित मापों के अनुसार किया जायेगा।

सारणी—I

क्र०सं०	उपाबन्ध-I के पैराओं के संदर्भ में	विशेषतायें	लॉट आकार	एक लॉट में परख किये जाने वाले नमूनों की संख्या	नमूना में दोषों की अनुज्ञेय संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	1 तथा 2	आकार तथा विमाएं	परेषण में एक ही प्रकार और आकार के सभी तामचीनी के बर्तन	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार
2.	3	कारीगरी तथा परिसज्जा	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3.	4.2	सामग्री तथा प्रतिघात प्रतिरोध परख	—यथोक्त—	2	शून्य
4.	4.3	शामक परख	—यथोक्त—	1	शून्य
5	4.4	लीक परख	—यथोक्त—	2	शून्य
6.	4.5	अम्ल प्रतिरोध परख	—यथोक्त—	2	शून्य

सारणी—II

एक लॉट में तामचीनी के बर्तनों की संख्या	नमूने का आकार	नमूनों के दोषों की अनुज्ञेय संख्या
150 तक	5	0
151 से 500	20	1
501 से 1000 तक	32	2
1001 से 3000 तक	50	3
3001 से 10,000 तक	80	5
10,001 तथा अधिक	125	7

सं० 6(20)/78/नि०नि०तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1978

S.O. 2909.—Whereas for the development of export trade of India certain proposals for subjecting Enamelwares to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1st October, 1977 under the order of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 3023 dated the 24th September, 1977.

And whereas objections and suggestions were invited till the 18th November, 1977 from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th October, 1977.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1277 dated the 25th April, 1966 the Central Government, after consulting the Export Inspection Council being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby—

(1) notified that Enamelwares shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specified the type of inspection in accordance with the Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1978 as the type of inspection which shall be applied to such Enamelwares prior to export;

(3) recognises the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for enamelwares subject to a minimum of the specifications as set out in the Annexure to this Order as the standard specifications for enamelwares;

(4) prohibits the export, in the course of international trade, of any such enamelwares unless the same is accompanied by a certificate issued by any of the agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such enamelwares satisfy the conditions relating to inspection and is exportworthy.

2. In this order "enamelwares" shall mean the articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) meant for domestic and hospital use.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air, of samples of enamelwares, the f.o.b. value of which does not exceed one hundred and twenty-five rupees to prospective buyers.

4. This order shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

ANNEXURE

[See Paragraph 1(3)]

SPECIFICATIONS OF ENAMELWARES

1. Material :

1.1 The Steel sheet should be of a gauge as per agreement between the buyer and the seller.

2. Shape and dimensions :

2.1 The design, dimensional details and capacity of enamelwares shall be as per agreement between the buyer and the seller. The tolerances on the same shall be as follows :—

Dimensions	—	±	2.5%
Capacity	—	±	2.5%

3. Workmanship and finish :

3.1 The surface of the wares shall not have any flaws like pinholes, cracks or crevices. The wares shall be reasonably free from warpage.

3.2 The enamelware shall have glossy or matt finish as per the agreement between the buyer and the seller and the colour, texture and thickness of enamel shall be evenly matched.

4. Tests :

4.1 The samples of enamelware shall meet the requirements of impact resistance test, quench test (for cooking wares only), leak test (for enamelware with joints only) and acid resistance test in accordance with the relevant national or international standard or as given in para 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5 below.

4.2 Impact resistance test.—A steel ball weighing 100 gm when allowed to fall freely from a height of 57 cm, on the surface of the anamelware, shall not produce any dent or large patch of peeler surface.

4.3 Quench test (for cooking wares only)—The specimen is to be heated to 185°C to 195°C for at least 10 minutes and quenched immediately in water at 15°C to 20°C. The cycle of heating and quenching is to be repeated for six times. The enamelled surface shall be examined for any signs of flaking off or crazing after undergoing six cycles test.

4.4 Leak Test—The enamelware shall be allowed to remain in water coloured with cosine for at least 10 minutes. During the test, there shall be no infiltration of coloured water to inside. The test shall be applicable for enamelwares with joints only.

4.5 Acid resistance test.—The surface of the enamelware shall be made free from dirt and grease by wiping with acetone and drying. A 3 cm. diameter thin filter paper shall be placed on the cleaned surface of the enamel, on the top of which a thicker filter paper of 2.5 cm. diameter shall be placed. Citric acid solution (100 gm./litre) shall be dropped on the filter papers until these are saturated. The filter paper shall be then covered with a watch glass to prevent evaporation. The filter papers shall be removed after ± 1 minutes and the surface shall be washed with running tap water and dried with a clean cloth. The enamel shall not show any perceptible change, that is to say there shall not be any loss of gloss. The mark of an HB pencil drawn across both the treated and untreated surface shall not be retained more by the one surface than by the other after they have been rubbed with a clean dry cloth.

5. Packing :

5.1 Enamelwares shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure the safe arrival of th wares to the destination without any damage.

5.2 The packages weighing upto 37 kg. shall be able to withstand a drop from a height of 150 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

6. Sampling and criteria for conformity:

Sampling and inspection of each consignment shall be done in accordance with the scale prescribed in Table I and II bellow:

TABLE I

Sl. No.	Reference to paragraphs in Annexure I	Characteristic	Lot size	No. of samples to be tested in a lot	Permissible No. of defectives in the sample
1.	1 and 2	Shape and dimension.	All enamelwares of same type and size in a consignment.	As per sampling schedule given in Table II	As per sampling schedule given in table II
2.	3	Workmanship and finish	—do—	—do—	—do—
3.	4.2	Material and impact resistance test	—do—	2	Nil
4.	4.3	Quench test	—do—	1	Nil
5.	4.4	Leak test	—do—	2	Nil
6.	4.5	Acid resistence test	—do—	2	Nil

TABLE II

No. of enamelwares	Sample size	Permissible No. of defectives in the samples
upto 150.	5	0
151 to 500	20	1
501 to 1000	32	2
1000 to 3000	50	3
3001 to 10,000	80	5
10,001 and above	125	7

[No. 6(20)/75-EI&EP]

का०आ० 2910—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा तामचीनी बर्तन निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम तामचीनी बर्तन निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है,

(ग) 'तामचीनी के बर्तनों;' से घरेलू तथा अस्पतालों के प्रयोग के लिये कॉचसम तामचीनी (पोसिलेन एनेमल) से बनी वस्तुएं अभिप्रेत हैं ।

3. निरीक्षण का आधार :—तामचीनी के बर्तनों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जायगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य तथा इन नियमों की अनुसूची में दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप हैं ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—तामचीनी के बर्तनों का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों की घोषणा किसी भी अभिकरण को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोतलदान की अनुसूचित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले दी जाएगी और इसके साथ ही सूचना की एक प्रति, निर्यात निरीक्षण परिषद् के निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी एक को देगा जो निरीक्षण के स्थान के निकटतम हो, अर्थात्:—

मुख्य कार्यालय — निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,' 14/1-बी, एज़रा स्ट्रीट, (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001

क्षेत्रीय कार्यालय —
1. निर्यात निरीक्षण परिषद् अमल चैम्बर्स (पांचवी मंजिल, 113, महर्षि कर्वे रोड़, मुम्बई-400004.
2. निर्यात निरीक्षण परिषद्, मनोहर बिल्डिंग्स, महात्मा गांधी रोड़, एर्नाकुलम्, कोचीन-682011
3. निर्यात निरीक्षण परिषद, म्यूनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, 3, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर अभिकरण नियम 3 तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार तामचीनी के बर्तनों का निरीक्षण करेगा ।

(4) (क) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही पैकजों को परेषण में इस रीति से सीलबंद करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मोहर बंद किए गए माल के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती ।

(ख) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता की इच्छा हो तो अभिकरण द्वारा परेषण को सीलबंद या मोहर बंद या स्टैनसील नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसी दशाओं में, निर्यात कर्ता की अस्वीकृत के विरुद्ध अपील करने का अधिकारी नहीं होगा।

(5) जहां अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि तामचीनी के बर्तनों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर निर्यातकर्ता को, इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है:

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता वहां वह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5. मान्यताप्राप्त चिन्हों का लगाया जाना और उसकी प्रक्रिया—निर्यात से पूर्व तामचीनी के बर्तनों पर मान्यता प्राप्त चिन्ह या सील लगाने की प्रक्रिया के संबंध में भारतीय मानक संस्था (प्रमाणकरण चिन्ह) अधिनियम 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणकरण चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्था (प्रमाणी चिन्ह) विनियम, 1955 के उपबंध में लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित किए हुए तामचीनी के बर्तन इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण के अधीन नहीं होंगे।

6. निरीक्षण का स्थान —इन नियमों के प्रयोजनों के लिए तामचीनी के बर्तनों का निरीक्षण या तो—

(क) विनिर्माता के परिसर पर ; या

(ख) उन परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

7. निरीक्षण फीस—निर्यातकर्ता द्वारा पच्चीस रुपए की न्यूनतम सीमा में रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए के लिए पचास पैसे की दर से फीस निरीक्षण के रूप में अभिकरण को दी जाएगी।

8. अपील—(1) नियम 4 के उप नियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र देने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात विशेषज्ञ होंगे।

(2) पैनल में विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

तामचीनी के बर्तनों के लिए विनिर्देश

1. सामग्री :

1.1 इस्पात की चादर का माप क्रेता तथा विक्रेता कर्ता के मध्य हुए करार के अनुसार होगा।

2. आकार तथा विमाएं

2.1 तामचीनी के बर्तनों का डिजाइन, विमाओं संबंधी विवरण तथा आगत क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करारनामें के अनुसार होंगे। उनकी सहायताएं निम्नलिखित के अनुसार होंगी।

विमाएं—	±2.5%
क्षमता—	±2.5%

3. कारीगरी तथा परिसज्जा

3.1. बर्तनों की सतह में कोई दोष जैसे विनछिन्न तड़कन या दरार नहीं होंगे। बर्तन विकुचंना से मुक्त होंगे।

3.2. तामचीनी के बर्तनों की परिसज्जा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य हुए करार शर्तों के अनुसार चमकदार या दयुतिहीन होगी तथा तामचीनी का रंग बनावट तथा मोटाई एक समान होंगे।

4. परखें :

4.1 तामचीनी के बर्तनों के नमूने सुसंगत राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मानक या नीचे दिये गए पैरा 4.2, 4.3, 4.4 तथा 4.5 के अनुसार प्रतिघात प्रतिरोध परख, शामक परख (केवल पकाने वाले बर्तनों के लिए), लीक परख (केवल जोड़ों वाले तामचीनी के बर्तनों के लिए) तथा अम्ल प्रतिरोध परख की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

4.2 प्रतिघात प्रतिरोध परख—जब तामचीनी के बर्तनों की सतह पर 100 ग्राम भार वाले इस्पात की गेंद को 57 सें० मी० की ऊंचाई से निर्बाध रूप से गिराया जाएगा तो बर्तन में कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा या गड्ढे वार सतह का कोई बड़ा निशान नहीं हो जाएगा।

4.3 शामक परख (केवल पकाने के बर्तनों के लिए)—नमूने को कम से कम 10 मिनट के लिए 185° सें० से 195° सें० तक गरम किया जाएगा तथा 15° सें० से 20° सें० तक पानी में तुरन्त बुझाया जाएगा। गर्म तथा बुझाने की क्रिया को छः बार दोहराया जाएगा। इनेमल की गई सतह का छह बार परख चक्रों में से निकालने के पश्चात् किसी भी प्रकार की पपड़ी के उतरने अथवा क्रेजिंग के किसी भी निशानों के लिए परीक्षण किया जायेगा।

4.4. लीक परख—तामचीनी के बर्तन को कम से कम 10 मिनट के लिए इओसाइन के रंगीन पानी में रखा जाएगा। परख के दौरान, रंगीन पानी बर्तन के भीतर नहीं घुसना चाहिए। यह परख केवल जो लगे तामचीनी के बर्तन को लागू होगी।

4.5 अम्ल प्रतिरोध परख—तामचीनी के बर्तन की सतह एसिटोन से पोंछ कर और सुखा कर गंदगी एवं चिकनाई से मुक्त की जाएगी। तामचीनी की साफ की गई सतह पर, 3 सें० मी० व्यास पतला फिल्टर कागज रखा जाएगा। जिसके ऊपर 2.5 सें० मी० व्यास का मोटा फिल्टर कागज रखा जाएगा। साइट्रिक एसिड घोल (100 ग्राम/लिटर) फिल्टर कागजों पर तब तक डाला जाएगा जब तक कि वे पूरी तरह तर न हों जाएं। तब फिल्टर कागजों को वाष्पीकरण से बचाने के लिए दृश्य कांच से ढक दिया जाएगा। 20±1 मिनट के पश्चात् फिल्टर कागज हटा लिए जाएंगे तथा सतह को नल के बहते हुए पानी में धिगोया जाएगा तथा साफ कपड़े से सुखाया जाएगा। तामचीनी में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् चमक में कोई कमी नहीं आएगी। साधित तथा असाधित दोनों ही सतहों पर एच० बी० पैंसिल से आर पार चिन्ह खींचा जाए तो साफ सूखे कपड़े से रगड़े जाने के पश्चात् एक सतह का चिन्ह दूसरी सतह के चिन्ह से अधिक देर तक नहीं रहेगा।

5. पैकिंग

5.1 तामचीनी के बर्तन क्रेता के अनुबंध के अनुसार इस ढंग से पैक किए जाएंगे जिससे कोई नुकसान हुए बिना बर्तनों का गन्तव्य स्थान तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाए।

5.2. 37 कि० ग्रा० तक के भार के पैकेज 150 सें० मी० की ऊंचाई से गिराने पर ठीक बने रहेंगे और पैकेज या उसमें रखे माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पैकेजों की मौसम के प्रतिकूल प्रभावों एवं आर्द्रता संघृषण से पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी।

6. अनुरूपता के लिए नमूना लेना तथा मापदण्ड

प्रत्येक परेषण का नमूना तथा निरीक्षण नीचे दी गई सारणियों I तथा II में वर्णित मापों के अनुसार किया जाएगा।

सारणी I

क्रम सं०	उपाबन्ध I के पैरों के संदर्भ में	विशेषतायें	लॉट आकार	एक लॉट में परख किये जाने वाले नमूनों की संख्या	नमूना में दोषों की अनुज्ञेय संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	1 तथा 2	आकार तथा विमायें	परीक्षण में एक ही प्रकार और आकार के सभी तामचीनी के बर्तन	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार	सारणी II में दी गई नमूना लेने की अनुसूची के अनुसार
2.	3	कारीगरी तथा परिसज्जा	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3.	4.2	सामग्री तथा प्रतिघात प्रतिरोध परख	—यथोक्त—	2	शून्य
4.	4.3	घातक परख	—यथोक्त—	1	शून्य
5.	4.4	लोक परख	—यथोक्त—	2	शून्य
6.	4.5	अम्ल प्रतिरोध परख	—यथोक्त—	2	शून्य

सारणी—II

एक लॉट में तामचीनी के बर्तनों की संख्या	नमूने का आकार	नमूनों के दोषों की अनुज्ञेय संख्या
1	2	3
50 तक	5	0
51 से 500	20	1
501 से 1000 तक	32	2
1001 से 3000 तक	50	3
3001 से 10,000 तक	80	5
10,001 तथा अधिक	125	7

[सं० 6(20)/75/नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 2910.—In exercise of the powers conferred by section of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 2 of 1963) and in supersession of the Export of Enamelwares spection) Rules, 1965, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Export of Enamelwares (Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) 'agency' means any of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act.

(c) 'Enamelware' means the articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) meant for domestic and hospital use.

3. Basis of Inspection—Inspection of enamelwares shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, and given in the Schedule to these rules.

4. Procedure of Inspection—(1) An exporter intending to export enamelwares shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration as to agreed specification of the export contract, to any agency to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than ten days before the scheduled date of shipment and a copy of intimation shall simultaneously be endorsed to any of the following offices of the Export Inspection Council which is nearest to the place of inspection, namely :—

Head Office : Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700 001.

Regional Office : 1. Export Inspection Council, Aman Chambers, 4th floor, 113, M. Karve Road, Bombay-400 004.

2. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-682 011.

3. Export Inspection Council Municipal Market Building, 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110 005.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the agency shall carry out the inspection of enamelwares in accordance with rule 3 and the instructions in this behalf issued by the Export Inspection Council from time to time.

(4) (a) After completion of the inspection, the agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with.

(b) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed or stamped or stencilled by the agency, but in such cases, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

(5) When the agency is satisfied that the consignment of enamelware complies with the requirement of the recognised specifications, it shall within three days of completion of inspection, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the conditions relating to inspection and is exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Affixation of recognised marks and procedure thereof—The provisions of Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 shall, so far as may be, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Enamelwares prior to export and Enamelwares so marked shall not be subjected to any inspection under rule 4 of these rules.

6. Place of inspection—Inspection of Enamelwares for the purpose of these rules shall be carried out, either—

(a) at the premises of the manufacturer ; or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for the purpose exist therein.

7. Inspection fee—Subject to a minimum of rupees twenty five, a fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of the F. O. B. Value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee.

8. Appeal—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven such experts as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE

SEE RULE 3

Specifications of Enamelwares

1. Material :

1. The Steel sheet should be of a gauge as per agreement between the buyer and the seller.

2. Shape and dimensions.

2.1 The design, dimensional details and capacity of enamelwares shall be as per agreement between the buyer and the seller. The tolerances on the same shall be as follows :—

Dimensions — ± 2.5 per cent.

Capacity — + 2.5 per cent.

3. Workmanship and finish :

3.1 The surface of the wares shall not have any flaws like pinholes, cracks or crevices. The wares shall be reasonably free from warpage.

3.2 The enamelware shall have glossy or matt finish as per the agreement between the buyer and the seller and the colour, texture and thickness of enamel shall be evenly matched.

4. Tests :

4.1 The samples of enamelware shall meet the requirements of impact resistance test, quench test (for cooking wares only), leak test (for enamelware with joints only) and acid resistence test in accordance with the relevant national or international standard or as given in para 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5 below.

4.2 Impact resistence test : A steel ball weighing 100 gm when allowed to fall freely from a height of 57 cm, on the surface of the enamelware, shall not produce any dent or large patch of peeler surface.

4.3 Quench test (for cooking wares only)—The specimer is to be heated to 185°C to 195°C for at least 10 minutes and quenched immediately in water at 15° to 20°C. The cycle of heating and quenching it to be repeated for six times. The enameled surface shall be examined for any signs of flaking off or crazing after undergoing six cycles test.

4.4 Leak Test—The enamelware shall be allowed to remain in water coloured with cosin for at least 10 minutes. During the test, there shall be no infiltration of coloured water to inside. The test shall be applicable for enamelwares with joints only.

4.5 Acid resistance test—The surface of the enamelware shall be made free from dirt and grease by wiping with acetone and drying. A 3 cm. diameter thin filter paper shall be placed on the cleaned surface of the enamel, on the top of which a thicker filter paper of 2.5 cm. diameter shall be placed. Citric acid solution (100 gm./litre) shall be dropped on the filter papers until these are saturated. The filter paper shall be then covered with a watch glass to prevent evaporation. The filter papers shall be removed after 20+ minutes and the surface shall be washed with running tap water and dried with a clean cloth. The enamel shall not show any perceptible change, that is to say there shall not be any loss of gloss. The mark of an HB pencil drawn across both the treated and untreated surface shall not be retained more by the one surface than by the other after they have been rubbed with a clean dry cloth.

5. Packing:

5.1 Enamelwares shall be packed in accordance with the stipulation of the buyer in such a manner as to ensure the safe arrival of the wares to the destination without any damage.

5.2 The packages weighing upto 37 kg. shall be able to withstand a drop from a height of 150 cm. without any damage to the contents inside or package itself. The packages shall also be adequately protected against adverse effects of weather and moisture contamination.

6. Sampling and criteria for conformity:

Sampling and inspection of each consignment shall be done in accordance with the scale prescribed in Table I and II below :

TABLE I

Sl. No.	Reference to paragraphs in Annexure I	Characteristic	Lot size	No. of samples to be tested in a lot	Permissible No. of defectives in the sample
1.	1 and 2	Shape and dimension	All enamelwares of same type and size in a consignment	As per sampling schedule given in Table II	As per sampling schedule given in table II.
2.	3.	Workmanship and finish	—do—	—do—	—do—
3.	4.2	Material and impact resistance test	—do—	2	Nil
4.	4.3	Quench test	—do—	1	Nil
5.	4.4	Leak test	—do—	2	Nil
6.	4.5	Acid resistence test	—do—	2	Nil

TABLE II

No. of enamelwares	Sample size	Permissible No. of defectives in the samples
upto 150.	5	0
151 to 500.	20	1
501 to 10 0	32	2
1000 to 3000	50	3
3001 to 10,000	80	5
10,001 and above	125	7

[No. 6(20)/75-EI&EP]

का०आ० 2911.—केन्द्रीय सरकार ने, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तामचीनी के बर्तनों के संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० 120 ओ० यू० आर० का० आ० 3024, तारीख 24 सितम्बर, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-II खण्ड-3 उप-खंड (ii) तारीख 1 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित किया था ;

और उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी लोगों से 18 नवम्बर, 1977 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 अक्तूबर, 1977 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1276 तारीख 25 अप्रैल, 1966 के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार यह द्योतन करने के प्रयोजन के लिए तामचीनी के बर्तनों के संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देती है कि जहां तामचीनी के बर्तनों पर ऐसे चिन्ह लगाए गए हों वहां वे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन उस पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाए।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में तामचीनी के बर्तनों से घरेलू तथा अस्पतालों के प्रयोग के लिए काचसम तामचीनी (पोर्सलिन इनेमल) से बनी वस्तुएं अभिप्रेत हैं।

[सं० 6(20)/75-नि० नि० तथा नि०
सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 2911.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) published a proposal to recognise the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to Enamelwares as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section 8 sub-section (ii), dated the 1st October, 1977, under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 3024, dated the 24th September, 1977 ;

And whereas the objections and suggestions were invited till the 18th November, 1977 from all persons likely to be affected thereby ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th October, 1977 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposal have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1276 dated the 25th April, 1966, the Central Government hereby recognises the Indian Standards Institution Certification Mark with respect to Enamelwares for the purpose of denoting that where Enamelwares are affixed with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under Clause (c) of section 6 of the said Act.

Explanation—In this notification 'Enamelwares' shall mean the articles made with vitreous enamel (porcelain enamel) meant for domestic and hospital use.

[No. 6(20)/75-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978